RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

# माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com


**सुविचार**

संघर्ष से भागो मत, क्योंकि संघर्ष से ही जीवन की मिठास आती है।

अटल बिहारी बाजपेयी


वर्ष-07, अंक - 45 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 07 अगस्त 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए


# तिरंगा हर देशभक्त के लिए आन, बान, शान, मगर विधायिका और कार्यपालिका के लिए अभियान

माही की गूंज। संजय भटेवरा

**झाबुआ।** वैसे तो देश भक्ति देश के हर नागरिक के रोम-रोम में भरी होती है, मगर देश की विधायिका और कार्यपालिका को यह लगता है कि, महज राष्ट्रीय पर्वों पर अभियान चलाकर लोगों को देशभक्ति सिखाई या जागृत की जाए। तो यह एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी ही कही जाएगी। क्योंकि साल दर साल आने वाले राष्ट्रीय पर्व हमें यह अहसास कराते है कि, हमारा देश किन हालातों और किन मुश्किलों का सामना करते हुए आजाद हुआ और हर बीतते साल के साथ हम स्वतंत्रता दिवस और उसकी वर्षगांठ मनाते आ रहे है। इस बार हम देश का 79 वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे है और यह हर देशभक्त के सीने में पहले से ही अंकित हो चुका है। हर देशवासी इस अवसर को लेकर गोरवान्ति महसूस कर रहा है कि, देश आजाद हुए हम आठवें दशक को पूरा करने की ओर बढ़ रहे है। मगर देश की विधायिका और कार्यपालिका अपने तथाकथित अभियानों से यह जताने की कोशिश कर रहे है कि, शायद हम अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय ध्वज को भूल चुके है। जबकि हर देशवासी के दिलों दिमाग पर यह अमिट स्याही से अंकित हो चुका है कि, हम कब आजाद हुए और हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व कोई आयोजन नहीं और ना ही तिरंगा कोई अभियान। यह तो हर देशभक्त का अहसास है कि, स्वतंत्रता हमें यूं ही थाली में परोस कर तो नहीं मिली, इससे जुड़ा बलिदान हमारी आत्मा के साथ जुड़ा है और तिरंगे की आन, बान और शान हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई है।

मगर वर्तमान स्थितियों में देश की विधायिका और कार्यपालिका इन राष्ट्रीय पर्वों पर जिस तरह से अभियान चला रहे है, वह देश के हर देशभक्त नागरिक पर उठाया गया प्रश्न चिन्ह है। जिला कलेक्टरों की स्वतंत्रता दिवस को लेकर ली जा रही बैठकें इसे प्रमाणित भी करती है।

तंत्र की जारी सूचनाओं को समझने की कोशिश में यह प्रतीत होता है कि, अभियान के पहले चरण में कार्यपालिका के निर्देशानुसार देशभक्ति के वातावरण का जागरण और तिरंगे पर केंद्रीत सार्वजनिक कार्यक्रम की रूपरेखा यह दर्शाते है कि, अब लोगों में देशभक्ति का जज्बा सो चुका है और कार्यपालिका अपने अभियान के जरिए उसे जगाना चाहती है। तिरंगे को अभियान बनाकर दूसरे चरण में लोगों को साथ जोड़ने का क्या ही मतलब निकाला जा सकता है। क्या देश के नागरिक वाकई तिरंगे से दूर हो चुके है...? हमारे नजरिये से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। महज तिरंगे के कुछ प्रोटोकॉल है जो हर देशभक्त को इसलिए बांधे रखते है क्योंकि कहीं राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान न हो जाए। वरना देशभक्ति और तिरंगे के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट करने के लिए महज भारतीय टीम का एक क्रिकेट मैच जितना ही काफी होता है। मगर यह सब देखने के लिए विधायिका और कार्यपालिका को खेलों की तरफ रूख करना पड़ेगा।

तो सवाल यह नही है कि, लोगों में देशभक्ति सो चुकी है, सवाल यह है कि, विधायिका और कार्यपालिका ने इसे किस तरह से जागृत कर रखा है। वैसे तो देशभक्त होने के लिए अब किसी बड़े बलिदान की आवश्यकता नही है, बस छोटे-छोटे कामों से भी आप अपनी देशभक्ति जाहिर कर सकते है। हर वह काम जो देश हित में हो वह करते चले जाएं। उदाहरण के तौर पर नशे से दूर रहे यह भी देश की तरक्की में आपका अहम योगदान ही है। क्योंकि नशे से दूर रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए यह भी आपकी देशभक्ति का प्रमाण हो सकता है। रिश्वत लेने और देने दोनों से ही बचे यह भी देश के विकास में आपका योगदान ही कहलाएग। मगर इसके विपरीत देश की विधायिका और कार्यपालिका की स्थिति बिल्कुल उलट है। जिस तरह से जिले में बैठे कलेक्टर देशभक्ति का राग अलापने और लोगों को देशभक्त बनाने में जुटे है वे अपने ही कार्यालयों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रहे है। यह कार्यपालिका की बहुत ही कमजोर कड़ी है। स्थितियां इतनी गंभीर है कि, कार्यालय के चपरासी से लेकर आला अधिकारी तक बिना कुछ लिए-दिए कोई काम ही नहीं करते। अब कल्पना कीजिए कि, भ्रष्टाचार के जिस दलदल में कार्यपालिका और विधायिका है, वह देश के आम नागरिक को जागरूक करने के लिए तिरंगा अभियान जैसे अभियान चला रही है।

होना तो यह चाहिए कि, इस तरह के अभियान से हटकर विधायिका में बैठे लोग और कार्यपालिका में विराजमान अधिकारी यह संकल्प लें कि, देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से पहुंचाएंगे और देश को विकसित बनाएंगे। यह एक ऐसा कदम होगा जो हर घर तिरंगा अभियान से ज्यादा प्रभावी होगा। मगर अफसोस यह है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका को महज अभियानों के नाम पर सरकारी खजाना खाली करना है और मीडिया से सुर्खियां बटोरना है। क्योंकि जबतक भ्रष्टाचार का बोलबाला होता रहेगा तब तक विधायिका और कार्यपालिका में बैठे लोगों के द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के अभियान ढकोसला मात्र ही साबित होंगे। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के अभियान किसी की देशभक्ति का आंकलन या देशभक्ति को लेकर उसकी जागृति को तो तय नहीं कर सकते।

मगर विधायिका और कार्यपालिका को यह तय करना ही पड़ेगा कि, वह किस ओर है...? भ्रष्टाचार और घपलों से देश को बर्बादी की ओर धकेलने के या फिर सिस्टम को सुधारकर, देशवासियों को भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त करा कर सच्ची देशभक्ति के साथ देश को विकास की ओर बढ़ाने कि ओर ले जाएगें। क्योंकि यही तय करेगा कि, विधायिका और कार्यपालिका अभियानों से हटकर असली देशभक्त है या नहीं...?

## ट्रम्प की धमकी का पीएम खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रहे- राहुल गांधी

**नई दिल्ली, एजेंसी।** कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को व्यापार संबंधी धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं।

श्री गांधी का कहना है कि ट्रंप भारत पर आयात शुल्क बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं, और प्रधानमंत्री की चुप्पी यह दिखाती है कि वे किसी दबाव में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका में चल रही अडानी समूह की जांच प्रधानमंत्री की मजबूरी बन गई है। गौरतलब है कि अमेरिका में अडानी समूह समेत कुछ भारतीय कंपनियों पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच हो रही है। बताया गया है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी सच में एक मजबूत नेता हैं, तो उन्हें ट्रंप की धमकियों का खुलकर जवाब देना चाहिए और देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को मित्रपूंजीवाद और विदेशी दबाव से जोड़ते हुए आगामी संसद सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बयान पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में गर्माहट बढ़ा दी है।

## किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन

**नई दिल्ली, एजेंसी।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन-03 का उद्घाटन किया। यह भवन बहुप्रतीक्षित सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है और सामान्य केंद्रीय सचिवालय (सीएसएस) की प्रस्तावित दस इमारतों में से पहली इमारत है।

इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत कर, प्रशासनिक कामकाज को अधिक तेज़, कुशल और समन्वित बनाना है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल एक भवन नहीं है, बल्कि ÷नए भारत के नए शासन मॉडल का प्रतीक÷ है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और फाइलों के लंबे इंतज़ार को समाप्त किया जा सकेगा। कर्तव्य भवन का निर्माण देश की प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक, कार्यकुशल और केंद्रीकृत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय जैसे प्रमुख विभागों के कार्यालय होंगे। कुल 51 मंत्रालयों को समाहित करने वाले दस केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है।

## मेक इन अमेरिका नीति से मेक इन इंडिया को बड़ा खतरा नहीं

**नई दिल्ली, एजेंसी।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी संरक्षणवादी नीतियों को आक्रामक तरीके से लागू करते हुए 'मेक इन अमेरिका' को वैश्विक व्यापार युद्ध का हथियार बना लिया है। भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने के साथ-साथ रूस से तेल खरीद को लेकर भी दबाव डाला जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि 'मेक इन अमेरिका' केवल एक आर्थिक योजना नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। वे चाहते हैं कि चिप से लेकर जहाज तक हर चीज़ अमेरिका में ही तैयार हो।

इसके तहत उन्होंने सभी देशों पर न्यूनतम 10 प्रतिशत आयात कर लगाने की घोषणा की है। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक आधार मजबूत होगा। हालांकि भारत ने इस नीति की तीखी आलोचना की है और कहा है कि व्यापार और विदेश नीति को मिलाकर ट्रंप वैश्विक मंच पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। भारत ने रूस से तेल खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए स्पष्ट किया है कि यह निर्णय भारतीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और वैश्विक ऊर्जा संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की ये नीतियां अमेरिका को दीर्घकाल में नुकसान पहुँचा सकती हैं। अमेरिका में अधिक श्रम लागत और उत्पादन खर्च के कारण वहाँ सस्ते उत्पादों का निर्माण संभव नहीं है। इसके विपरीत भारत जैसे देशों में सस्ती श्रमशक्ति, कम उत्पादन लागत और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता ने उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। पूर्व वाणिज्य सचिव के अनुसार ट्रंप की आयात शुल्क नीति से 'मेक इन इंडिया' को कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि अमेरिका की लागत प्रणाली वैश्विक निर्माण क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती।

## साइबर ठगी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

**नई दिल्ली, एजेंसी।** देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई, जो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) पर आधारित है। ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने लगभग 260 करोड़ रुपये की बड़ी राशि बिटकॉइन के रूप में कई क्रिप्टो बटुए (पर्स) में जमा की। बाद में इस राशि को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हवाला के जरिए अमेरिकी डॉलर टेदर (यूएसडीटी) में बदला गया और नकद में परिवर्तित कर लिया गया।

यह खुलासा इस अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क की गहरी पहुंच को उजागर करता है। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लेकर देहरादून तक ईडी की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ संदिग्ध ठिकानों की तलाशी में जुटी हैं। इस अभियान का उद्देश्य न केवल सबूत जुटाना है, बल्कि इस साइबर ठगी गिरोह को पूरी तरह समाप्त करना भी है। जांच में यह भी सामने आया कि, आरोपियों ने भारतीय और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया। ये ठग खुद को पुलिस या जांच अधिकारी बताकर लोगों को गिरफ्तारी की धमकी देते थे और उनकी संपत्तियों को हड़प लेते थे। पीड़ितों से ठगी गई रकम को डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) में बदला गया और फिर वह राशि गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाई गई।

## फैक्ट्री में गैस सिलेंडर विस्फोट, 2 की मौत, 4 घायल

**मोहाली।** पंजाब के मोहाली जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाली फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकानों की दीवारें कांप गईं और फैक्ट्री की छत को भारी क्षति पहुंची।

विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सिलेंडर के टुकड़े एक किलोमीटर दूर तक जा गिरे। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें जांच में जुटी हुई हैं।

मृतकों की पहचान आसिफ खान और देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है, दोनों की आयु लगभग 25 वर्ष थी और वे कंबाला गांव के निवासी थे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से लगातार घटना की जानकारी ले रहे हैं।

घटना जिस स्थान पर हुई, वहां ऑक्सीजन संयंत्र है, जहां से चंडीगढ़-त्रिकेंद्र (ट्राइसिटी) क्षेत्र सहित पूरे पंजाब के अस्पतालों में सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती है। बताया गया है कि हादसे के समय वहां सिलेंडर भरे जा रहे थे, तभी अचानक एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा के मद्देनज़र मौके से सभी सिलेंडर हटाए गए।

यह विस्फोट इतना भयानक था कि मृतकों के शव के अंग भी दूर-दूर तक बिखर गए। फैक्ट्री का नाम हाइटेक उद्योग बताया गया है, जो एक पुरानी इकाई है। सिलेंडर के टुकड़े एक किलोमीटर दूर स्थित कंबाला गांव तक जा पहुंचे।

# स्वाधीनता दिवस हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक- मुख्यमंत्री

**भोपाल।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वाधीनता दिवस केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय पहचान, आत्मगौरव और सम्मान का प्रतीक है। यह अवसर हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, बलिदान और योगदान को स्मरण करने तथा उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

डॉ. यादव बुधवार को स्वाधीनता दिवस समारोह-2025 के आयोजन से जुड़ी तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में तय किया गया कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता के नाम दिए जाने वाले संदेश का सभी जिलों में होने वाले जिला स्तरीय समारोहों में सीधा प्रसारण किया जाएगा।

डॉ. यादव ने कहा कि जनता के नाम संदेश के प्रसारण के बाद प्रत्येक जिले के कार्यक्रम में

मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में जिले की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों, निवेश, कृषि, सिंचाई और अन्य उपलब्धियों के बारे में नागरिकों को जानकारी देंगे।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला स्तरीय समारोहों का आयोजन पूरे उत्साह, गरिमा और जन भागीदारी के साथ किया जाए। विशेष रूप से युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। डॉ. यादव ने राज्य स्तरीय समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों, दिव्यांग नागरिकों, वरिष्ठजनों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे स्वाधीनता दिवस समारोह में सम्मिलित होकर देशभक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुँचाएँ।

बैठक में मंत्रियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर होने वाले समारोहों में गरिमा के अनुरूप नवाचारों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए।

## पहले उत्तरकाशी अब हिमाचल में फटा बादल

**किन्नौर।** उत्तरकाशी में तबाही के बाद अब हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के तंगलिंग क्षेत्र में बुधवार को बादल फट गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसका एक भयावह चित्रण सामने आया है जिसमें पहाड़ से चट्टानें और मलबा तेज़ी से बहते हुए सड़क पर गिरते दिखाई दे रहे हैं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इस आपदा का सबसे बड़ा प्रभाव कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पड़ा है। बाढ़ की वजह से दो पुल बह गए और अन्य रास्ते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। कई श्रद्धालु मार्ग में फंसे हुए हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की टीम ने रस्सी के सहारे एक-एक करके 413 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। राहत कार्य जारी हैं।

इसी दौरान किन्नौर के रिब्बा गांव के पास रालडांग खड्ड में भी बादल फटने की जानकारी मिली है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर लगभग 150 मीटर तक कीचड़ और बड़े-बड़े पत्थर जमा हो गए हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

वहीं, चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार रात को भू-स्खलन हुआ, जिससे मार्ग बाधित हो गया है। राज्य भर में 500 से अधिक सड़कें बंद पड़ी हैं। शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू जिलों में सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है।

बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं हैं। उत्तराखंड के धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से चार लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कर्णप्रयाग में पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, वहीं हरिद्वार-देहरादून रेल मार्ग पर चट्टान गिरने से रेल संचालन भी ठप हो गया है।

प्रशासन और आपदा राहत टीमें स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की टीमें सक्रिय हैं।

# कौन है रचना दयाल सिंह ? जिसने स्थानांतरण के नाम पर डॉक्टर से कर डाली ढाई लाख की वसूली

## डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अभी तक बयान दर्ज करवाने नहीं पहुँचा, नहीं हो पाई कायमी

## कहीं विभागीय सांठ-गांठ की पोल खुलने के डर से तो नहीं किया रिपोर्ट का नाटक

**माही की गूंज, पेटलावद।**

स्वास्थ्य विभाग पेटलावद में सामने आए फर्जी स्थानन्तरण आदेश के मामले में अब तक किसी प्रकार का मामला दर्ज नही हुआ है । मामला अत्यंत गम्भीर होकर भोपाल के बड़े अधिकारीयो की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जहां पेटलावद विकास खण्ड के बेंगनबड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर अरुण कुमार बेरागी ने इस फर्जी आदेश मामले को घुमा कर खुद के साथ ठगी होना बताया। तथा सारंगी चौकी और पुलिस अधीक्षक झाबुआ के समक्ष आवेदन पेश कर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन अब तक मामले में कोई कायमी नही हुई है।

### आखिर कौन है रचना दयाल सिंह ?

बेंगनबड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर अरुण कुमार बैरागी ने अपने आवेदन में बताया कि विगत चार वर्षों से विभागीय पोर्टल पर विधिवत आवेदन कर रहा हूँ। इस वर्ष भी, शासन के पोर्टल पर नियमानुसार आवेदन किया था। पोर्टल पर आवेदन करने के कुछ दिन बाद, डॉक्टर के मोबाइल नंबर पर एक महिला का व्हाट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाली महिला ने स्वयं को 'रचना दयाल सिंह' बताया और कहा कि, वह मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। महिला ने डॉक्टर बताया कि आपके द्वारा पोर्टल से किया गया मेरा स्थानांतरण आवेदन मंजूर हो गया है, लेकिन इसके लिए मुझे 'स्थानांतरण का खर्च' स्वयं वहन करना होगा। मुझे यह सुनकर संदेह हुआ, और मैंने उसे बताया कि मैं उसे नहीं जानता और मेरी जानकारी में स्थानांतरण का कोई खर्च नहीं लगता। इस महिला कहा कि भुगतान ऑनलाइन होगा और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उसने यह भी कहा कि यदि शासन आदेश करती है तो शासन खर्च उठाती है, लेकिन यदि मैं स्वयं स्थानांतरण करवाना चाहता हूँ, तो मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के नाम पर आवेदन देकर अपने स्वयं के खर्च पर स्थानांतरण करवाना होगा ।

### परिचितो से पुष्टि के बाद भुगतान किए 50हजार, फिर आदेश के नाम पर वसूले दो लाख

डॉक्टर के अनुसार शंका होने के बाद रतलाम स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ चचेरे भाई अभिषेक बेरागी और रामलाल भगोरा से मुलाकात की। जिंसमे रामलाल भगौरा ने बताया कि, वे 'रचना दयाल सिह' नाम की उक्त महिला को जानते हैं, जो इंदौर में लाल हॉस्पिटल में पदस्थ है और उनके साथ अध्ययनरत थी। रामलाल भगोरा की जानकारी अनुसार महिला फर्जी नहीं है और मेरे पास आया फोन एक विभागीय प्रक्रिया का ही हिस्सा है और इसी के बाद रामलाल भगोरा के माध्यम से रचना दयाल को आवेदन बनाकर भिजवा दिया। इसके बाद, दिनांक 10 जुलाई 2025 को, उसने अपने नंबर देकर फोन पे पर पैसे डालने को कहा। चूंकि समस्त लेनदेन ऑनलाइन था और महिला परिचित रामलाल भगोरा की परिचित थी इसलिए पचास हजार रुपये स्थानांतरण खर्च के नाम पर उक्त महिला के मोबाइल नंबर 8319055197 डॉक्टर ने पचास हजार फोन पे के माध्यम से उसे भेज दिए।

उप स्वास्थ्य केंद्र बेंगनबड़ी में पदस्थ डॉक्टर अरुण कुमार बैरागी।

### आदेश की प्रति दिखा कर वसुले दो लाख

महिला ने पचास हजार वसूलने के बाद डॉक्टर को पुनः फोन लगा कर कहा कि, आदेश की प्रति सीधे विभाग को भेज दी जाएगी, जिसके बाद मुझे 2 लाख रुपये और जमा करवाने होंगे। डॉक्टर ने पैसे देने से इनकार कर दिया डॉक्टर के अनुसार उक्त महिला ने पैसे देने से इनकार करने पर धमकी दी कि यदि मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा, तो पूर्व में दिए गए पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे और मेरा स्थानांतरण कहीं दूर करवा दिया जाएगा। इस धमकी के बाद डरे हुए डॉक्टर ने महिला को पैसे देने की हा कर दी। पैसे की डील तय होते ही उक्त महिला ने रामलाल भगौरा के मोबाइल नंबर 8435954658 पर डॉक्टर के स्थानांतरण आदेश की प्रति भेजी और कहा कि यह आदेश मेरे विभाग में तभी आएगा जब दो लाख रुपये मिलेगे । डॉक्टर ने महिला के बताए अनुसार एक लाख रुपये मोबाइल नंबर 6261808008 ग्लोरी लाल को 19 जुलाई 2025 को, पचास हजार रुपये मोबाइल नंबर 8319055197 रचना सिंह को 19 जुलाई 2025 को और पचास हजार रुपये 9111426216 हिमांशु सिंह को 20 जुलाई 2025 को फोन पे के माध्यम से डाल दिए। जिन नम्बरों पर भुगतान हुवे वो महिला के परिवार के सदस्य बताए जा रहे है।

### भुगतान मिलने के बाद आदेश पहुँचा रामलाल के पास

आवेदन में डॉक्टर ने बताया कि भुगतान होने के बाद महिला रचना सिंह दयाल ने परिचित रामलाल भगोरा को आदेश कि प्रति मोबाइल पर भेज कर उनको कहा कि वे इस आदेश को अरुण दास बैरागी को भेजकर रिलीज़ आदेश ले लें और शासन द्वारा जिला मुख्यालय पर आदेश भिजवा दिया गया है।

### धोखाधड़ी का लगाया आरोप

डॉक्टर अरुण कुमार बेरागी ने महिला पर धोखाधड़ी आरोप लगाते हुए बताया कि विभागीय प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसा हुआ है । मैं उक्त आदेश लेकर जब डॉक्टर विभाग में पहुँचा ताकि तथाकथित आदेश की पुष्टि करने पर जानकारी हुई कि मेरे साथ धोखाधड़ी करके पैसे ले लिए गए हैं, और जिसे डॉक्टर विभागीय प्रक्रिया मान रहा था वह वास्तव में एक बड़ा धोखा निकला। डॉक्टर ने 'रचना दयाल सिंह' और उसके सहयोगियों 'ग्लोरी दयाल' और 'हिमांशु सिंह' के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

### पुलिस ने कहा बयान दर्ज करने कोई नही आया

मामला बहार आने के बाद गूंज ने इस खबर की पूरी पड़ताल की ओर प्रमुखता से खबर प्रकाशित करते हुए पूरा मामला उजागर करते हुए है ये शंका व्यक्त की थी इस मामले को विभाग कोई कार्यवाही नही करते हुवे मामले को रफा दफा कर सकता है । क्योकि इस मामले में मुख्य रूप से सामने आरही महिला रचना दयाल सिंह कई बड़े राज ओर नाम खोल सकती है जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ओर स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों के चहरे बेनकाब हो सकते है । मामले में विभाग की और से फर्जी आदेश लेकर कार्यमुक्त होने की कोशिश करने वाले डॉक्टर पर कोई कार्यवाही नही की गई और पुलिस चौकी सारंगी के चौकी प्रभारी दीपक देवरे से इस संबद्ध में बताया कि मामले में जांच करने के लिए बयान के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया लेकिन कोई भी बयान दर्ज करवाने अभी तक नही आया। हमारे द्वारा डॉक्टर अरुण कुमार बेरागी से संपर्क कर कारवाई की जानकारी चाही गई तो डॉक्टर ने कोई जानकारी नही दी और ऑफिस पर आकर मिलने की बात कह कर फोन काट दिया।

## प्रथम कार्डियोलॉजिस्टः गांव के मासूम ने जिले का नाम किया रोशन

**माही की गूंज, सारंगी।**

गाव सारंगी से मासूम तलेसरा अपने सफर की शुरुआत कर आज ना सिर्फ अपना व अपने परिवार का, अपने गाव का अपितु अपने पूरे जिले का नाम रोशन किया। कक्षा 12वीं के बाद सिधे पीएमटी के द्वारा चयनित होकर नेताजी सुभाषचंद्रबोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर से एमबीबीएस (गोल्ड मेडल विजेता ) पूर्ण कर, अगले 1 वर्ष के लिए सिविल अस्पताल पेटलावद में भीषण कोरोना काल में अपनी सेवाऐ दी। जिसके बाद अगले 6 माह जिला चिकित्सालय रतलाम और तीन माह बाजना अपनी सेवा देकर फिर से अपनी राह पर खुद को तराशने निकल पड़े। एक बार फिर अपनी योग्यता के आधार पर नीट पीजी की परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज,उज्जैन से एमडी की डिग्री प्राप्त कर अपने क्षेत्र को गौरवान्वित किया । प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गाव के एक स्कूल से शुरू होकर कदम से कदम बढ़ाकर आज अपने जिले झाबुआ से प्रथम कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए सिम्स ,इंदौर मे चयनित होकर डीएम कार्डियोलॉजी करने निकल पड़े। डॉक्टर मासूम तलेसरा कि इस उपलब्धि पर गांव के वरिष्ठ नागरिको एवं नगर पत्रकार संघ ने बधाई दी। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की।

डॉ मासूम तलेसरा

## राखी पर्व पर स्वच्छता का विशेष अभियान

**माही की गूंज, थांदला।** स्वच्छता रैंकिंग में फिसलने के बाद निकाय ने नगर को नंबर वन बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा रक्षाबंधन के पूर्व महिला पार्षदों एवं महिला सफाई कर्मियों द्वारा संपूर्ण नगर में स्वच्छता के लिए नवीन अभियान का श्री गणेश वार्ड क्रमांक 01से किया। रक्षाबंधन के पूर्व देश के प्रधानमंत्री की फोटो अंकित वाली राखी जिसपर मेरा वचन स्वच्छ थांदला का स्लोगन लिखा था। उसे हर प्रतिष्ठान पर जाकर व्यवसायियों को महिला पार्षदों द्वारा तिलक लगा कर राखी बांध कर एक वचन लिया कि, आज के बाद मैं, मेरे प्रतिष्ठान सहित घर को, नगर को स्वच्छ रखूंगा। साथ ही परिषद के कचरा वाहन में ही गिला व सूखा कचरा नियमित रूप से वाहन में ही डालूंगा।

इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सुनील पणदा ने नगर के नागरिकों से आव्हान किया कि, नगर को सही मायने में स्वच्छ बनाना है तो हर व्यक्ति को मन से स्वच्छता अपनानी होगी। कार्यक्रम में नगर परिषद के जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

## कार्यकारिणी सभा का आयोजन

**माही की गूंज, थांदला।** पूज्य श्री जिनेन्द्रमुनिजी म.सा. के कुशल निर्देशन में पूज्य श्री धर्मदास गण परिषद के माध्यम से गण के सकल जैन श्रीसंघों में नियमित आराधना का क्रम बनाने व साधर्मी सेवा संकल्पों को पूरा करने के उद्देश्यों को लेकर संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत भंसाली के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पूज्य प्रवर्तक देव की आज्ञानुवर्ती शासन प्रभाविका महासती पूज्या श्री संयमप्रभाजी म.सा. आदि ठाणा के सानिध्य में नागदा (कानवन) में गण की द्वितीय कार्यकारिणी सभा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत भंसाली (थांदला), महामंत्री शैलेश पीपाड़ा (रतलाम), राष्ट्रीय प्रवक्ता देवेंद्र गादिया (इन्दौर) व संघ अध्यक्ष अभिषेक मोदी (नागदा) के आतिथ्य में आयोजित की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में वर्ष 2025-26 त्रिरत्नों की सुमाला के अंतर्गत संघ में हो रही व्यक्तिगत व पारिवारिक वार्षिक सामयिक आराधना, पक्खी मण्डल की स्थापना, प्रतिक्रमण कंठस्थ करने व गण व युवा संगठन की सदस्यता विस्तार के साथ ही आगामी वर्ष 2026-27 के लिए आराधना की कार्ययोजना बनाना था। गण परिषद के द्वितीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पदाधिकारियों की समस्त संघों में प्रवास यात्रा की समीक्षा भी हुई। वही गण का ट्रस्ट रुप में पंजीयन करवाने व आगामी सामूहिक वर्षीतप आराधना के पारणें के लिए पारणा स्थल, आवास व्यवस्था, टेंट, भोजन आदि अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विषयों पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर माधवाचार्य परीक्षा मंडल सहित गण के आय-व्यय का ब्यौरा गण के कोषाध्यक्ष संतोष चपलौद व सह कोषाध्यक्ष दीपक रुनवाल ने प्रस्तुत किया।

# अब नहीं रहेगी गांव में वोल्टेज की समस्या

### विद्युत विभाग में पुरानी केबल हटाने के बाद नई केबल डालना करी शुरू

**माही की गूंज, भामल।**

खवासा विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले रन्नी फिटर के ग्राम भामल में पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों को कम वोल्टेज की समस्याओं से जुझना पड़ रहा था। पूर्व में जो केबल लगाई गई थी वह कम मापदंड की थी। जिसकी वजह से बार-बार लाइन फाल्ट हो रही थी तो ग्रामीणों को विद्युत के लिए परेशान होना पड़ रहा था। जिससे ग्रामीणों को सही समय पर विद्युत लाइन नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि रंन्नी फिटर में घरेलू व सिंचाई के लिए एक ही लाइन होने से ग्रामीणों को वोल्टेज की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा था। जिसको देखते हुए झाबुआ विद्युत विभाग के अंतर्गत आने वाले खवासा क्षेत्र में आरडीएसएस के तहत केंद्र सरकार की पुर्नत्थान योजना के अंतर्गत ग्राम भामल में एक नया ट्रांसफॉर्म लगाया जा रहा है । साथ ही जो पुरानी केबल 45 से 50 एमएम की थी उसको बदलकर 95 से 100 एमएम की नई केबल डाली जा रही है अभी कार्य प्रगति पर है। जिसमें ग्राम भामल में चार दिन से दिन में लाइट भी केबल बिछाने के दौरान काटी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि, माही की गूंज ने कम वोल्टेज की समस्या को लेकर पूर्व में कई बार समाचार प्रकाशित किए थे। जिसके बाद प्रशासन व विद्युत विभाग के अधिकारियों ने नए सिरे से इस्टीमेन्ट बनाकर ग्राम भामल में तीन नए ट्रांसफॉर्मर स्वीकृत करे। इसके बाद नए सिरे से लाइन डालना शुरू हो चुकी है। जो मजदूर काम कर रहे हैं इन्होंने बताया है कि, पूरे गांव में खम्बे लगाने के साथ ही नई केबल डाल दी गई है और रक्षाबंधन के बाद इसको सुचारू रूप से विद्युत लाइन शुरू कर दी जाएगी।

जानकारीनुसार केबल व खम्बे लगाने का ठेका आर,वी,एल,एन भिंड की कंपनी को मिला है। खवासा एमपीबी मे पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर मुकेश परमार ने माही की गूंज को चर्चा मे बताया कि, बहुत ही जल्द गांव में तीन नए ट्रांसफॉर्म लगा दिए जाएंगे अभी केबल का कार्य चल रहा है। भामल में पूरी तरह से 24 घंटे विद्युत लाइन सुचारू रूप से मिल पाएगी इसी को देखते हुए शासन ने यहां नए सिरे से केबल डालने का कार्य शुरू किया है। वही अब यहां के ग्रामीणों को वोल्टेज की समस्या से जुझना नहीं पड़ेगा।

# नए भवनों के इंतजार में देश के भविष्य का किराए के कमरे में लग रहे स्कूल

## नए भवन स्वीकृत नहीं हुए, एक कमरे में लग रहा पूरा स्कूल

**माही की गूंज, बरवेट। जगदीश प्रजापत**

जिले की कई प्राथिमक विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से संसाधनों की कमी और प्रशासनिक उपेक्षा की शिकार होती नजर आ रही है। एक वर्ष पूर्व शासकीय विद्यालयो को जर्जर घोषित कर भवनों को प्रशासन ने गिरा तो दिया, लेकिन अब तक वहां नए भवन तैयार नहीं किए गए। स्थिति यह है कि कई गांवों में बच्चे अन्य जगह पढने को मजबूर है। वही आंगनबाड़ी या निजी भवनों के एक कमरे में पूरा स्कूल समेट दिया गया है। बरवेट संकुल के अंतर्गत छह प्राथमिक विद्यालय को गिराकर जमीदोज कर दिया है। इधर विभाग का का कहना है कि हमने भवनों को मांग भेज दी है स्वकृत मिलते ही कार्य प्रारंभ किया जाएंगे। गौरतलब है की पुरे जिले में 201 जर्जर स्कूल भवनों को गिराए गए है। उनको गिराने के बाद नए भवनों स्वीकृत नही हुए है। जिससे बच्चों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इससे बच्चों की शिक्षा में बाधा आ रही है और उनके लिए सुरक्षित और उपयुक्त वातावरण नही मिल पा रहा है।

एक कमरे में 50 से अधिक बच्चे बैठ कर पढ़ने पर मजबूर।

### 50 अधिक बच्चे एक ही कमरे में

ग्राम पंचायत महुडीपाडा कला के पंच भरत बंजारा ने बताया कि गोठानिया की प्रा.वि. भवन को जमीदोज करने के बाद आंगनवाड़ी में विद्यालय संचालित किया जा रहा है। दोनों संस्था के लगभग 53 बच्चों को बिठाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे भविष्य संवरेगा। बिना नए भवनों को स्वीकृत करवाये जर्जर भवनों को गिरा दिया गया अब एक साल बाद भी नए भवन स्वीकृत नहीं हुए हैं, जिससे बच्चों को किराए या अन्य भवनों में कक्षाएं लग रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा आ सकती है।वरिष्ठ भाजपा नेता बामनिया ने कहा कि जिम्मेदारों को शीघ्र ही भवन स्वीकृत करने चाहिए।

अर्जुन पटेल कांग्रेस नेता बोडायता ने बताया कि जर्जर भवन बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते थे, यदि उन्हें गिराने के एक साल बाद नए भवन नहीं बने हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। स्कूल में सुरक्षा छात्रों को मिलती है वह अन्य भवन में नही मिल सकती। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए अविलम्भ भवन स्वीकृत होने चाहिए।विपुल लोढ़ा कांग्रेस नेता बरवेट ने बताया कि पुर्व में शिक्षा के मंदिरों को चिन्हित कर जमींदोज किए गए थे, परंतु 01 साल पूर्ण होने पर भी अभी तक भवन स्वीकृत न होना निचले स्तर पर शिक्षा के प्रति जवाबदेही तय न होना जीता जागता उदाहरण देखा जा रहा है। सरकार को जर्जर भवनों को गिराने के साथ-साथ नए भवनों को शीघ्र स्वीकृत करना चाहिए।

जर्जर भवन जमीदोज होने के बाद स्थिति जस की तस, नए भवनों का इंतजार

### 201 जर्जर भवन को गिराया

जिले के अंतर्गत 201 जर्जर एव पुराने स्कूल भवन को जमीदोज कर राज्य शिक्षा केन्द्र को स्वीकृति के लिए भेज दिए है। परंतु वहाँ से स्वीकृति नही मिली है। एचसी मैडा उपयंत्री सर्व शिक्षा अभियान झाबुआ ने बताया कि जिला कलेक्टर ने खनिज विभाग की राशि मे से 25 भवन के लिए स्वीकृति दी है। जिनके टेंडर लगने के बाद कार्य प्रारम्भ किए जाएंगे। वही 15 भवनों की स्वीकृति के लिए कलेक्टर महोदय ने जानकारी मांगी है। स्वीकृत भवनों की संख्या 40 हो जाएगी।

# क्या बदल जाएगी पेटलावद विधानसभा की तस्वीर, कावड़ यात्रा चुनावी एंट्री गेट

## जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में निकली विशाल कावड़ यात्रा, मंत्री नागरसिंह चौहान भी हुए शामिल

कावड़ यात्रा का स्वागत करते मंत्री नागरसिंह चौहान, साथ मे पेटलावद के वरिष्ठ भाजपा नेता।

विशाल कावड़ यात्रा के बाद आयोजित धर्म सभा।

जनपद अध्यक्ष रमेश सोंलकी।

**माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत**

**पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बनते-बिगड़ते रहते है। यहां से विधायक निर्मला भुरिया व वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। वर्षो से पेटलावद विधानसभा भाजपा और निर्मला भूरिया का गढ़ रहा है। लेकिन क्षेत्र और कार्यकर्ताओं से दूरी अब निर्मला भुरिया के स्वामित्व पर खतरा बन कर मंडराने लगे है। आने वाले समय मे राजनीतिक सरगर्मीयो पर विशवर्त चर्चा होगी। फिलहाल सावन माह में निकलने वाली कावड़ यात्राओं के नाम पर हो रहे शक्ति प्रदर्शन और क्षेत्र में तेजी से उठती नये चेहरे की मांग ने नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है।**

### जनपद अध्यक्ष की कावड़ यात्रा बनी राजनीतिक चर्चा का विषय

पूर्व सांसद गुमानसिंह डामोर ने पेटलावद क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपनी एंट्री इस क्षेत्र में लेने के लिए श्रावण माह में निकलने वाली कावड़ यात्रा को ही माध्यम बनाया था। ओर वंदे मातरम ग्रुप को पर्दे के पीछे से सहयोग कर पेटलावद विधानसभा में एंट्री मार कर लगभग पेटलावद विधानसभा का टिकिट हासिल कर लिया था। लेकिन पार्टी में दिलीप सिंह भूरिया के ब्रांड नाम से नही जीत पाए और आखिर पेटलावद छोड़ कर झाबुआ विधानसभा का टिकिट लेना पड़ा था। उसी तर्ज पर जनपद अध्यक्ष ही कावड़ यात्रा को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि रमेश सोलंकी इस यात्रा को केवल धार्मिक और प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला आयोजन बता रहे है। पर क्षेत्र के वरिष्ठ ओर युवा नेताओं का मानना है कि, अब समय परिवर्तन का है और फिलहाल रमेश सोलंकी इस साँचे में फिट बैठ रहे है। सोमवार को जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी के नेतृत्व में टिमरिया-करडावद होकर पेटलावद नीलकंठेश्वर महादेव तक निकली कावड़ यात्रा में उमड़ी हजारों कावड़ियो की भीड़ को लेकर राजनीति गर्मा गई है। और हर कोई रमेश सोलंकी को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से सफल आयोजन को लेकर बधाई संदेश साथ ही आगमी विधानसभा चुनाव में दावेदारी हेतु भी प्रोत्साहित कर रहे है।

### नागरसिंह की एंट्री ने डाला तड़का...

मंत्री नागरसिंह चौहान और मंत्री निर्मला भूरिया के बीच चल रही खींचतान किसी से छुपी नही है। मंत्री चौहान खुल कर महिला बाल विकास में होने वाली भर्ती में लेन-देन को लेकर बयान दे चुके है। वही सांसद अनिता नागरसिंह चौहान से क्षेत्र की बढ़ती उम्मीदो के चलते मंत्री निर्मला के क्षेत्र हस्तक्षेप और बढ़ती लोकप्रियता भी मंत्री भूरिया को अखर रही है जिसकी चर्चा तक कार्यकर्ता के बीच सुनी जा सकती है। ऐसे में मंत्री नागरसिंह चौहान की रमेश सोलंकी की कावड़ यात्रा में एंट्री ने एक बार और राजनीतिक हलचल तेज कर दी। हालांकि यात्रा के लिए निर्मला भुरिया भी आमंत्रित थी लेकिन भोपाल होने के कारण शामिल नही हो पाई। नागरसिंह चौहान ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और उनका भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओ ने खूब स्वागत किया। कावड़ यात्रा की समाप्ति पर आयोजित धर्म सभा को भी सम्बोधित किया।

### कावड़ यात्रा बनी चुनावी इंट्री गेट

केवल भाजपा या कांग्रेस के लिए ही नही कावड़ यात्रा किसी भी छोटे बड़े चुनाव में उतरने के लिए इंट्री गेट बन चुकी है। जहां कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक वालसिंह मैंडा जगह-जगह कावड़ यात्रा निकाल रहे है। तो इस मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके मालू अकमाल डामोर भी कावड़ यात्रा निकाल रहे है और कावड़ यात्राओं का भव्य स्वागत कर रहे है। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य अजमेर भूरिया भी बड़ी कावड़ यात्रा के माध्यम से चुनावी ताल ठोक चुके है। रमेश सोलंकी भी प्रतिवर्ष कावड़ यात्रा निकाल कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे है।

### बागी होकर मैदान में उतर चुके है सोलंकी

क्षेत्र में नये चेहरे और पेटलावद क्षेत्र से प्रत्याशी की मांग के चलते जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी विधानसभा चुनाव 2023 में बागी होकर मैदान में उतर पड़े थे। विधानसभा चुनाव हेतु अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ पहुँच कर नामांकन फार्म भी लिया लेकिन उनके कुनबे में शामिल कई नेता खुल कर सामने नहीं आये। अंत मे पार्टी के बड़े नेताओं के दबाव में पार्टी द्वारा तय प्रत्याशी निर्मला भुरिया के समर्थन में उतर कर उनके साथ नामांकन फार्म जमा करने पहुँच कर उनके चुनाव लड़ने के कयासों को विराम लगा दिया था। अब नए परिसीमन के बाद विधानसभाओ की क्या स्थिति बनती है। उसी के बाद नए समीकरण बनते दिखाए देगे।

**गूंज असर पर कार्रवाई ढुलमुल**

# झोलाछाप डॉक्टर पर प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ नोटिस-नोटिस का खेल रहा खेल

## अनदेखीः घरों के अंदर बना लिए क्लिनिक, खटिया व पलंग डालकर चढ़ा रहे हैं स्लाईन

**माही की गूंज, खवासा/भामल। सुनिल सोलंकी**

ग्रामीण क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा इलाज के नाम पर भोले भाले लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना ही इलाज का कोई अनुभव। अगर किसी के पास जो डिग्री है उसको भी उसी पद्धति से इनको इलाज करना है। लेकिन यह एमबीबीएस व एमडी की तर्ज पर ग्रामीण अंचलों में एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर रहे हैं। वहीं मरीजों को भर्ती करने के साथ उनके दवाँखाने में खटिया पर बोटल व स्लाईन, इंजेक्शन आदि लगा रहे है। जिससे कई बार मरीजों की मौत तक हो रही है। लेकिन फिर भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी व प्रशासन इनके ऊपर कारवाई करने के बजाय इनका संरक्षण देता हुआ नजर आता है। ग्रामीण अंचलों में लोगों को अवैध चिकित्सक हाई डोज दे रहे हैं व अवैध तरीके से लूटा जा रहा है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी शासन ने दे रखी है वह तो इनसे मिलीभगत करके मामले को ठन्डे बस्ते में डाल रहे हैं। वहीं ग्रामीण मजबूरी वश इन से इलाज कराने को मजबूर है। खवासा क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह से अवैध चिकित्सक कुकुरमुतो की तरह जमे हुए हैं। इनको प्रशासन का जरा भी डर नहीं है।

माही की गूंज ने पिछले अंक में प्रमुखता से इनके समाचार प्रकाशित किया गया था। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कि सिर्फ नोटिस का खेल, खेला गया।

नियमों की बात करे तों कोई भी प्रैक्टिशन या क्लीनिक संचालित करने से पहले जिला स्वास्थ्य कार्यालय या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से इनको अनुमति लेना रहती है। बिना रजिस्ट्रेशन के अपना क्लीनिक संचालित नहीं कर सकते।

खवासा में पदस्थ डॉक्टर राकेश निनामा के अनुसार, खवासा मे 16 से 17 अवैध चिकित्सक निजी तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके पास झाबुआ जिला स्वास्थ्य अधिकारी से कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। बिना अनुमति के यह अपना क्लीनिक संचालित कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई बैठक में इनको अभी नोटिस दिए गए हैं। खवासा में 17 अवेध चिकत्सक व लेब सहित आस-पास भामल, कुकड़ीपाड़ा आदि जगह इनको नोटिस दिया गया है।

8 दिन के अंदर इनको सीएमएचओ कार्यालय मे अपनी वैध डिग्री लेकर रजिस्ट्रेशन कराना है। और जो पद्धति से यह इलाज कर सकते हैं उसी पद्धति से इनको इलाज करना है। अन्य पद्धति से अगर यह इलाज करते पाए गए तों इनके ऊपर वैधानिक आयुर्विज्ञान अधिनियम के तहत धारा 24 के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी।

# झाबुआ को धार जिले से जोड़ने वाला रोड डबल लाइन से वंचित क्यों...?

**माही की गूंज, बक्की। ऋषभ गुप्ता**

पेटलावद तहसील के एकमात्र रोड जो रायपुरिया से भक्ति गांव, जुना पानी फोरलेन को जोड़ता है यह रोड टूलेंन से क्यों वंचित है। जबकि पेटलावद तहसील में आने वाले गांव में सभी दूर टू लेन रोड बन चुके है।

रायपुरिया से बोलासा, बोलासा गांव से दो रोड निकलते हैं। जिसमें एक रोड़ विश्व मंगल धाम तारखेड़ी से हो कर जाता है। यहां प्रति मंगलवार हजारों श्रद्धालु दूर-दूर से हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं और बोलासा से एक रोड झकनावदा के लिए जाता है। जहां माही नदी के तट पर स्थित श्रृंगेश्वर धाम भोलेनाथ का वर्षों पुराना मंदिर है। जहां श्रावन मास में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। माही नदी के तट पर स्थिति यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि, माही माता के संगम में स्नान करने से लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है और माही नदी के संगम में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने पर उन्है मुक्ति मिल जाती हैं।

रायपुरिया से जूना पानी व्याहा बोलासा, झकनावदा मार्ग पर दो-दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने से काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती है। कई लोगों ने तो दुर्घटना में अपनी जान भी गवा दी है। मगर सरकार का इस रोड पर क्यों ध्यान नही है। जबकि प्रदेश और देश में एक ही सत्ता का बोलबाला है इस क्षेत्र से भाजपा के सांसद और विधायक दोनों ने जीत हासिल की और सत्ता में कुर्सी प्राप्त की। मगर फिर भी इस रोड के साथ सांसद विधायक का सौतेला व्यवहार क्यों...?

झकनावदा में स्थित टप्पा तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव में अधिकांश किसान वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिन्हें राजस्व के कामों के लिए आए दिन झकनावदा टप्पा तहसील पर जाना पड़ता है। जिस वजह से भी इस रोड पर आवागमन रहता है और सिंगल रोड होने से दुर्घटनाओं का अंदेशा हर समय बना रहता है।

यदि रायपुरिया से बनी तक रोड की बात की जाए तो इस रोड की हालत भी जर्जर हो चुकी है। रोड पर बड़े-बड़े गड्ढो में तब्दील हो चुका है। गांव में प्रवेश करते ही गटरों का पानी आए दिन रोड पर बहता मिलता है। गांव के अंदर रोड की स्थिति जर्जर हो चुकी है।

# चयनित स्कूलों मे आई शौचालय की मरम्मत की राशि मे भी बंदरबाट

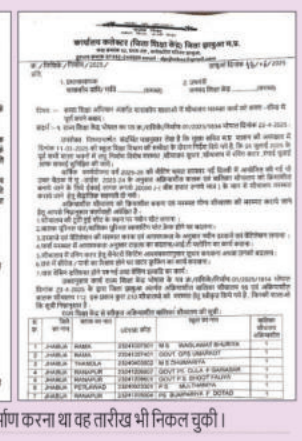

शौचालय का फोटो जो इस तरह अभी भी पड़े है। वह आदेश जिस आदेश मे इनको निर्माण करना था वह तारीख भी निकल चुकी।

**माही की गूंज, खवासा। सुनील सोलंकी।**

एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार निर्मल भारत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। तो वहीं जहां शौचालय नहीं है उन शौचायलयों में नए सिरे से निर्माण के साथ मरम्मत की राशि भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत शासन द्वारा चयन नीति शिक्षा विभाग की स्कूलों में दी जाती है। जिससे कि, बालक-बालिकाओं को शौचालय में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। इसी को देखते हुए प्रत्येक शौचालय के मान से झाबुआ जिले की थांदला विकासखंड के अंतर्गत खंड शिक्षा कार्यालय से एक आदेश से राशि स्वीकृत हुई है। जिसमें गर्मी में ही इनको जुलाई से पहले शौचालय में मरम्मत के साथ मेंटेनेंस करके उस राशि का सही उपयोग करना था। बताते हैं, कि मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा इन चयनित संस्थानों में शाला प्रबंधन समिति के खाते में 20-20 हजार के मान से शौचालय की राशि स्वीकृत हुई है। इनको 1 जुलाई से पहले शौचालय में मरम्मत जिसमें नल फिटिंग, शौचालय में रंगाई-पुताई के साथ ही जहां बेसिंग के साथ पानी की व्यवस्था के लिए टंकी आदि टूटे हुए हैं उन्है भी रिपेयर करना था। लेकिन कुकड़ीपाड़ा संकुल के अंतर्गत आने वाली करंजपाड़ा माध्यमिक विद्यालय, परवाड़ा नाका फलिया, भामल संकुल के अंतर्गत आने वाले कसाड़िया, मकोडिया फलिया में शौचालय में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जहां कार्य किया गया है वहां सिर्फ रस्म निभाई गई है। जबकि शौचालय में गंदगी पड़ी हुई है। ऐसी अन्य शालाओं में भी अभी तक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्य नहीं किया गया और राशि आहरण कर ली गई है। केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत होने के बाद अगर इस तरह से राशि में भ्रष्टाचार हो रहा है तो विभागीय अधिकारियों को देखना चाहिए कि, आखिर धरातल पर किस स्तर का कार्य शिक्षकों ने बच्चों की सहूलियत के लिए किया है या नहीं। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर वह सुविधा बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुहया करने का दावा कर रही है। जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण के लिए पहुंचे। लेकिन यहां मरम्मत के लिए आई राशि में भी बंदर बांट कर दी गई। बताते हैं कि, सभी जगह शाला मे शाला प्रबंधक के खाते में से राशि आहरण कर ली गई है, लेकिन धरातल पर शौचालय में कार्य नहीं किया गया है। और जहां कार्य किया गया है वहां सिर्फ रस्म निभाई गई है। पुराने शौचालय को छोटा-मोटा कार्य करने के बाद उसमें आज भी कहीं जगह शौचालय में बेसिन, नल फिटिंग नहीं है। जबकि बीस हजार की राशि से इनका पूरा का पूरा निर्माण करना था।

## तिरंगा यात्राः बाइक रैली को लेकर बैठक आयोजित

**माही की गूंज, सारंगी।** 15 अगस्त को लेकर इस वर्ष भी एक बार फिर राष्ट्र प्रेम का यह महा अभियान पूरे देश में गूंज रहा है। प्रदेश ओर जिला नेतृत्व के आदेशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी मंडल सारंगी में काम-काजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आमंत्रित अतिथियों को पुष्प मालाओं से स्वागत सत्कार किया गया ओर बैठक में नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष पप्पू लाल गामड़ ने स्वागत भाषण दिया। उसके पश्चात तिरंगा यात्रा प्रभारी जितेंद्र गेहलोत व विधानसभा संयोजक हैमंत भट्ट ने तिरंगा यात्रा को लेकर अपनी विस्तार से अपनी बात रखी व तिरंगा यात्रा के मार्ग ओर यात्रा को किस प्रकार भव्यता के साथ संपन्न करवाया जा सके पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, जेष्ठ, श्रेष्ठ ओर सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी मिडिया प्रभारी सुरेश चंद्र परिहार ने दी।

## मंदिर को बनाया चोरों ने निशाना , चुराए आभूषण

**माही की गूंज, बामनिया।** समीपस्थ ग्राम रामपुरिया में स्थित पंच मुखी हनुमान मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार चोरों ने पंचमुखी मंदिर परिसर में स्थित राम दरबार स्थित भगवान के दो चाँदी के मुकुट एवं माताजी का चाँदी का कंदोरा चोर ले गए । सूचना के बाद मौके पर बामनिया पुलिस ने जांच की ,एसडीओपी एवं डॉग स्कावड ने पहुँच कर मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तफ्तीश शुरू की । बारिश के समय मे चोरी का भय बना रहता है और सुने मकान ओर मंदिर चोरों के निशाने पर होते है।

## संपादकीय

# पहाड़ों के विकास मॉडल पर हो पुनर्विचार

मानसून की दस्तक के साथ ही हिमाचल व उत्तराखंड में दरकते पहाड़ व रौद्र रूप दिखाती नदियां चिंता बढ़ाने वाली हैं। कुदरत के कहर के सामने इंसान बौना ही नजर आता है। तमाम मुख्य नदियां उफान पर हैं। जगह-जगह भूस्खलन से सड़कें ठप पड़ी हैं। हिमाचल में मूसलाधार बारिश के बीच मलबा व पत्थर गिरने से सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पहले हम गर्मी से त्रस्त होकर बारिश की आस लगाए होते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो स्थितियां डराने वाली हो जाती हैं। निस्संदेह ग्लोबल वार्मिंग संकट के चलते बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। बारिश कम समय में ज्यादा मात्रा में बरसती है। जिससे न केवल पहाड़ों में कटाव बढ़ जाता है बल्कि पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा गिरकर रास्तों व पानी के प्राकृतिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। यह संकट इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमने पहाड़ों को विलसिता का केंद्र बना दिया है। तीर्थाटन अब पर्यटन जैसा हो गया है। पर्यटकों के वाहनों से छोटी सड़कें और पुल दबाव में हैं। नीति-नियंताओं ने पहाड़ों में सड़कों को फोर लेन-सिक्स लेन बनाने का जो उपक्रम किया है, उससे पहाड़ों का नैसर्गिक वातावरण खतरे में है। पहाड़ों के किनारे काटने से भूस्खलन की गति तेज हुई है। गाहे-बगाहे पहाड़ों का मलबा सड़कों पर गिरकर यातायात को अवरुद्ध कर देता है। यात्रियों के जीवन पर हर समय संकट बना रहता है।

हिमाचल की ही तरह से कुदरत के कोहराम से उत्तराखंड भी बुरी तरह त्रस्त है। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी व पिंडर आदि नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ने से यात्रा कुछ समय के लिये स्थगित की गई है। बार-बार भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। जगह-जगह सड़कों के कटने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बह गई हैं। बादल फटने की आशंका भी लगातार बनी रहती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री जाने वाले मार्ग जगह-जगह बाधित हैं। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। सामान्य जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई मोटरमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हुए हैं। कई छोटे पुल बह गए हैं। कई निचले स्थानों से लोगों को हटाया गया है। कुल मिलाकर लाखों लोगों को अतिवृष्टि ने बंधक बना दिया है। निश्चित रूप से तेज बारिश और उसके प्रभाव इंसानी नियंत्रण से बाहर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद पहाड़ी इलाकों में विकास के मॉडल पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। पहाड़ अध्यात्म के केंद्र भी रहे हैं, उन्हें पर्यटकों की विलसिता का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अपेक्षाकृत नये हिमालयी पहाड़ों और उसके परिस्थितिकीय तंत्र के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियों का बढ़ा जल संकट का कारण भी बन रहा है।

# लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित भारतीय वैश्विक नीति

जनरल एस.एस. मेहता

उपनिवेशवाद न केवल धन-दौलत लूटता है, बल्कि गरिमा भी खंडित कर देता है। यह पराधीन राष्ट्रों को खुद पर संदेह करना, अपने सहज ज्ञान को नकारना और मान्यता पाने को दूसरे देशों की ओर तकना सिखाता है। भारत के लिए, यह घाव महज चुराए गए अन्न या लूटे गए खजाने का नहीं था। यह मानसिकता में कहीं ज्यादा गहरे तक बदलाव करने वाला रहा- यह धारणा बना देना कि शासन, व्यवस्था और नैतिकता विदेशों की देन है।

तथापि, जब स्वतंत्रता मिली, तो भारत ने अपने उत्पीड़कों का अनुकरण नहीं किया। इसने प्रतिशोध को सिद्धांत या बहिष्कार को नीति के रूप में नहीं अपनाया। विभाजन की राख में, भीषण गरीबी और टुकड़े हुए उपमहाद्वीप के बीच, भारत ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया - अपने लोगों पर पूर्णतया भरोसा करने का। केवल पुरुषों पर ही नहीं, पढ़े लिखों पर ही नहीं, केवल पैसे वाले अमीरों पर नहीं बल्कि सभी पर। वयस्क नागरिकों के लिए समान मताधिकार कोई क्रमिक रियायत नहीं थी। यह आधारभूत हक था। अमेरिका द्वारा मताधिकार अधिनियम पारित करने से भी पहले, कई यूरोपीय मुल्कों द्वारा अपने नागरिकों को पूर्ण मताधिकार प्रदान करने से भी पूर्व, भारत अपने प्रत्येक नागरिक को आवाज़ दे चुका था। अपने जन्म के समय से ही, हमारा लोकतंत्र एक उधार लिया हुआ विचार न होकर सभ्यतागत सत्यापना थी।

लेकिन समय का अपना तरीका है नैतिक स्मृति की परीक्षा लेने का। आज, वही शक्तियां जो कभी हमें लिबर्टी का पाठ पढ़ाया करती थी, अब अपनी उन्हीं लोकतांत्रिक नसीहतों पर कायम रहने के लिए हाथ-पैर मार रही हैं। जिन बाज़ारों को उन्होंने कभी मुक्त बनाया था, अब उसी को डिजिटल दीवारों और टैरिफ बैरिकेड्स की ढाल के पीछे महफूज बना रही हैं। सबके लिए जिस स्वतंत्रता का कभी वे जोर-शोर से प्रचार करती थीं, अब चुन-चुनकर राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगा रही हैं, इसमें सहयोगियों को छूट तो अन्य को नहीं। करुणा सशर्त बन गयी। व्यापार जोर-ज़बरदस्ती करने का औजार बन गया है।

अब यदि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मुक्त बाज़ार पर हमला कर रही हैं, आवाज़ों को दबा रही हैं, टैरिफ का बाजा बजा रही हैं, तुरत-फुरत महानता पाने को, आतंकवादी शासनों से दोस्ती कर रही हैं और अपनी ही दी नैतिक नसीहतों को दरकिनार कर रहीं, तब फिर उन हस्ताक्षरों का क्या मोल, जो वे सकंल्पपत्रों पर और सम्मेलनों में बड़े गर्व से करती हैं?

बहुपक्षीय मंचों में, हम देखते हैं कि घोषणाओं को साजिशन कुंद किया जाता है। मानवाधिकारों को लाभ उठाने के औज़ार होने तक सीमित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के वादे दोहराए जाते हैं, लेकिन फिर चुपचाप एक तरफ सरका दिए जाते हैं। शरणार्थियों का अमानवीयकरण किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर खुलेआम बेजा पुलिसिया दबाव रखा जा रहा है। युद्धों का मूल्यांकन उनकी मानवीय कीमत से नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि हथियार किसके हाथ में है।

इस बीच, भारत कई लोगों के लिए पहेली बना हुआ है। विकासशील और लोकतांत्रिक। कुछ गड़बडियां है, फिर भी वजूद कायम है। विशाल, फिर भी शायद ही कभी साम्राज्यवादी हसरतें। हमने उन लोगों का तिरस्कार अंगीकार किया जिन्हें हमारे तौर-तरीके की समझ नहीं थी। हमने उन लोगों की उदासीनता को झेला है जिन्होंने हमारी आवाज़ को खारिज कर रखा था। फिर भी अपने लोगों और दुनिया के साथ बनाए मौन अनुबंध में हमने अपना विश्वास नहीं खोया। हम परिपूर्ण नहीं हैं। खामियां हममें भी हैं। लेकिन हम दिखावा नहीं करते। और यही अंतर मायने रखता है।

वैश्विक व्यवस्था में हमारी आमद इसके पाखंडों की विरासत अपनाने के लिए नहीं हुई। हम इसकी निराशावादिता को प्रतिबिंबित करने की एवज में मंच पर अपनी जगह नहीं चाहते। और हमें उनके भाषण की कतई जरूरत नहीं है जो यादों को सुविधानुसार बरतते हैं और न्याय को सौदेबाजी के औजार के रूप में। हमारे संयम को अक्सर मौन समझा जाता है व हमारी सभ्यता को दासता प्रवृत्ति। लेकिन भारत के सभ्यागत दिशा सूचक की सुई वैश्विक स्वीकृति की तरंगों मुताबिक नहीं हिलती। इसकी जड़ें बैलेंस शीट और शिखर सम्मेलन की घोषणाओं से कहीं गहरी हैं। आत्म-सुधार इसका जन्मजात गुण है। और अब, जबकि दुनिया अपने ही अंतर्विरोधों के बोझ तले चरमरा रही है, तो प्रलोभन दिया जाएगा कि हम पीछे हट जाएं, दूसरों को पुनः दुनिया की इबारत तय करने दें और विनम्र सम्मानवश सहमति का सिर हिलाते रहें। लेकिन वह युग बीत चुका है।

हाथी की यादाश्त बहुत होती है: उसे 1947 याद है, जब हमने अधिनायकवादी शासन की बजाय लोकतंत्र को चुना। उसे 1971 याद है, जब पड़ोस में नरसंहार के खिलाफ अकेले हम खड़े हुए थे। उसे 1991 याद है, जब हमने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था, बल्कि अपने आत्मविश्वास का भी पुनर्गठन किया था। उसे 1998 याद है, जब साधन संपन्न राष्ट्र परमाणु ताकत को वैश्विक श्रेष्ठता का पैमाना मानते थे, और विशिष्ट समूह में हम जबरदस्ती घुसे, किंतु परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल न करने की घोषणा की। और दुनिया ने हाल में ऑपरेशन सिंदूर देखा।

हमने जो भी किया, संयम और संकल्प इसकी कुंजी रही। हमने महाशक्तियों की घुड़कियां सुनी, आक्रामकता भरी भौंक सुनी, अवसरवादिता की तीखी चीखें भी। लेकिन दुनिया ने अभी तक हाथी की चिंघाड़ नहीं सुनी है, युद्धघोष के रूप में नहीं, बल्कि स्मृति, नैतिकता और दिशा का आह्वान करने वाली।

वह समय अब आ गया है: इसलिए नहीं कि हम कुछ थोपना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें नकल करने से इन्कार है। वार्ता में हावी होने के लिए नहीं, बल्कि उसे किसी ऐसे ठोस लंगर से बांधने को, जो मुनाफे की बजाय चिरकालिक अधिक हो।

पाखंडवाद की नई रणनीति: बात करो मूल्यों की पर काम करो स्वहित का। यूक्रेन को लेकर आवाज़ उठाओ, किंतु गाज़ा पर नज़रें फेर लो। एक अत्याचारी पर प्रतिबंध लगाओ तो दूसरे को सलाम बजाओ। मुक्त व्यापार के नाम पर उन हुकूमतों के साथ भी साझेदारी करो, जहां असल राजकाज सैन्य वर्दी के हाथ में रहता है और बदलाव की मांग करने वाले अपने ही नेताओं को कैद कर लेती है। भारत दहाड़ता नहीं, न ही गरजता है। गूंजता भी नहीं लेकिन उसे सब याद है। और जब अंततः बोलता है, गुस्से में आकर नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ, तो वह दूसरों को डुबोने की कोशिशें नहीं करता। केवल उन्हें याद दिलाने की खातिर।

ऐसे में, जब लोकतंत्र अपने ही प्रतिबिंब को धुंधला करने लगे हैं, सैन्य शासनों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, निर्वासनों पर आंखें मूंद रखी हैं, और ताकतवरों में अपनी सुविधा खोज रहे हैं। तब खतरा हो गया है उन आदर्शों को त्यागने का जिनका वे कभी निर्यात करते थे। जब रणनीतिक पहुंच की कीमत दमन पर चुप्पी साधना बन जाए, जब सैन्य पंचाट व्यवस्था का अलम्बरदार होने का चोला ओढ़ ले, और जब शासन व्यवस्था सुधारकों का वेश बनाए गुप्त-पारिवारिक अभिजात वर्ग की पालतू बन जाए, तब राष्ट्र और उसकी जनता के बीच नाता लोकतांत्रिक नहीं रहता, वंशवादी हो जाता है। यह केवल कुछ लोगों के लिए ही टिकाऊ बन जाता है।

हाथी की चिंघाड़: हमारी साझेदारियां लेन-देन आधारित नहीं हैं। हमारी मित्रताएं अंधी नहीं हैं। हम दुनिया के साथ जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की कीमत पर नहीं जिनके पास न आवाज़ है, न वोट, न स्रोत क्योंकि स्मृति महज वह नहीं जो कुछ हमें याद रहे। यह उस बारे में है, जो बनना हमें मंजूर नहीं।

हाथी भूलता नहीं: उसके पास गरिमा और मुक्त बाज़ार में मांग के बीच फंसे हुए 140 करोड़ लोग हैं। वह पिछलग्गू नहीं है। वह आईने की भांति प्रतिबिम्ब दिखाता है। कब चलना है और कब चिंघाड़ना है, यह खुद तय करता है।

# दक्षिण एशिया से संतुलन बिगाड़ते ट्रंप के फैसले

ज्योति मल्होत्रा

इस मानसून की एक सुबह को, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किए जाने की घोषणा किए जाने के बाद, इसका अहसास 1999 में कारगिल में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद की सुबहों जैसा रहा दृ शांति बनने का किंतु लगभग अवास्तविक। सिवाय इसके कि इस बार मामला उलट है। तब जुलाई 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल क्लिंटन से दृढ़ता से कह दिया था कि वे नवाज़ शरीफ़ तक बात पहुंचा दें - जिनसे क्लिंटन की मुलाकात वाशिंगटन डीसी में कारगिल युद्ध को खत्म के प्रयास में होने जा रही थी - कि भारत समझौता तभी करेगा जब आखिरी पाकिस्तानी सैनिक उस नियंत्रण रेखा पार कर वापसी करेगा, जिससे होकर उसने कश्मीर में घुसपैठ की थी। नवाज़ शरीफ़ के पास राजी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। और कारगिल संघर्ष समाप्त हो गया। और एक साल बाद, जब क्लिंटन भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर आए, जयपुर में उनपर बरसाई गई गुलाब की पंखुड़ियों से सराबोर हो गए, लौटते वक्त वे पांच घंटे पाकिस्तान में रुके।

बीते सप्ताह, भारत ने अमेरिका की नीतियों में बदलाव से पाकिस्तान की तरफ बनते झुकाव की समीक्षा की दृ बदलाव जो इतना नाटकीय है कि अगर पहले से इसका अनुमान न होता तो भारतीय प्रतिष्ठानों में, वाशिंगटन डीसी से लेकर नई दिल्ली तक, किसी की नौकरी जाने की नौबत बन जाती दृ इसके तहत, पाकिस्तान अक्तूबर में अमेरिका के साथ फिर से मजबूत हुई दोस्ती को दस लाख बैरल तेल आयात करके रेखांकित करेगा।

1989 के बाद से पहली बार - जब आखिरी सोवियत सैनिक ने अफगानिस्तान से वतन वापसी की थी और उसके तुरंत बाद, काबुल से नास्तिक कम्युनिस्टों को खदेड़ने की जीत से उत्साहित हुए अमेरिकियों ने पाकिस्तानी सेना को हथियार और डॉलरों की बहती धारा रोक दी थी - अमेरिकी अब फिर से पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं। यह अंतहीन बड़े खेल में पासा एक बार फिर पलटने जैसा है, लेकिन इस बार भारत को नुकसान होना तय है।

सनद रहे कि पाकिस्तान चीन का सहयोगी है। यह भी याद रखें कि ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत चीन पर बेतहाशा टैरिफ लगाकर की थी क्योंकि उन्हें अहसास है कि चीन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पैरों तले से जमीन सरका दी है व चीन की बजाय अमेरिका में वापस उत्पादन करना 'अमेरिका को पुनः महान बनाने' के सकंल्प के लिए अहम है।

लेकिन ट्रंप ने बीते हफ़्ते पाकिस्तान के साथ समझौता करके और भारत पर 'मृत अर्थव्यवस्था' का तंज कसकर दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का बिंदु बदल दिया है। शायद वाशिंगटन डीसी की गर्मी या तो मार-ए-लागो में उनके द्वारा खाए किसी व्यंजन का असर है कि वे भूल गए कि महज पांच साल पहले, ह्यूस्टन में मोदी ने 'अबकी बार, ट्रंप सरकार' का नारा लगाया था, जिससे ट्रंप को अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों की बहुमूल्य वोटें मिली होंगी।

ट्रंप के सत्ता के खेल से अंतर्राष्ट्रीय बिसात का स्वरूप निश्चित तौर पर बिगड़ जाएगा। यह कहना जल्दबाज़ी होगा कि पिछली सदी के शीत युद्ध के पुराने दोस्त 21वीं सदी के इसके नए प्रारूप के इर्द-गिर्द फिर एकजुट होने लगे हैं। परस्पर वार्ताएं जारी हैं, खासकर क्वाड बैठकों में दृ जिसका शिखर सम्मेलन नवंबर में दिल्ली में होगा यानि ट्रंप का आना तय है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मोदी को रूस के पक्ष में धकेलने ('भारत व रूस की मृत अर्थव्यवस्थाएं' ) के बाद, उनके पास व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रगाढ़ता बनाने के सिवा शायद ही कोई विकल्प हो।

दोस्ती और विदेश नीति बराबर की हैसियत वालों के बीच निभती है। यही कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच असामान्य गलबहियां, केवल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच ही नहीं थी, या इसलिए भी नहीं कि भारतीय मूल के अमेरिकी तरक्की करते हुए अमेरिका के सबसे प्रभावशाली समूहों में एक बन गए बल्कि यह मित्रता इसलिए भी थी कि आर्थिक असमानता के बावजूद, दोनों परस्पर समकक्षों जैसा व्यवहार करने से डरते नहीं थे।

भले ही आइज़नहावर में इसकी समझ नहीं रही लेकिन रुज़वेल्ट को भारत की विशिष्टता का भान था। कैनेडी इसे बखूबी समझते थे - उनके मित्र और भारत में तत्कालीन राजदूत, जॉन केनेथ गैलब्रेथ की एक तसवीर चंडीगढ़ के गवर्नमेंट म्यूजियम की ऊपरी मंज़िल पर स्थित छोटे से पुस्तकालय में, उस स्तंभ के दूसरी ओर टंगी है, जिस पर एमएस रंधावा की तसवीर टंगी है दृ हालांकि विदेश मंत्री किसिंजर नहीं समझते थे। और 1971 में, जब किसिंजर ने पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखने का बचाव खुलेआम किया और 1971 में पश्चिम बंगाल में एक करोड़ बांग्लादेशियों के पलायन की आलोचना की थी, तब पूर्व शीर्ष रक्षा विश्लेषक के. सुब्रह्मण्यम उन्हें फटकार लगाने से डरे नहीं? (हालांकि 1998 के परमाणु परीक्षणों के परिप्रेक्ष्य में, जब माहौल कुछ ठंडा पड़ा, तो अमेरिका में भारतीय राजदूत नरेश चंद्रा व किसिंजर दोस्त बन गए।)

इसका उल्टा भी सच था। वाजपेयी को अमेरिका की महत्ता का भान था - हालांकि भारत द्वारा 1998 के परमाणु परीक्षणों पर अमेरिकी गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था फिर भी वे दोनों देशों को 'नैसर्गिक सहयोगी' बताते थे। फिर जब मनमोहन सिंह ने जॉर्ज बुश से कहा- 'भारत आपसे प्यार करता है'- तो अमेरिका ने 2008 के परमाणु समझौते के बाद भारत को अनाधिकारिक रूप से परमाणु राष्ट्रों के विशिष्ट क्लब में शामिल कर लिया। पीएम मोदी ने भी, 2020 में 'अब की बार, ट्रंप सरकार' वाली जुगत के साथ समझ लिया था कि व्हाइट हाउस पहुंचने की राह गुणगान है। इसलिए, यह समझ से परे है कि विदेशमंत्री एस. जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर विवाद समाप्त करने का श्रेय ट्रंप को न देने पर क्यों अड़े हैं, जबकि ट्रंप न्यूनतम 15 बार ऐसा दावा कर चुके हैं। (इसके उलट घाघ पाकिस्तानियों ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामांकित कर दिया।)

भारत-पाकिस्तान मामलों में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को भारत सदा अस्वीकार करता आया है और 1972 के शिमला समझौते की द्विपक्षीय राह सर्वोपरि मानता है। लेकिन तब क्या ,जब भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संवाद से इनकार कर दे।

9-10 मई की रात, माना जाता है, जब पीएम मोदी ने अचानक 11 पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी का आदेश दे दिया। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई ने पाकिस्तानियों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अमेरिकियों को और अमेरिकियों ने जयशंकर को फोन किया। जयशंकर ने कहा- 'पाकिस्तानियों से कहो कि वे सीधे हमसे यह कहें'। फिर 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय समकक्ष को फोन किया और दोनों पक्ष टकराव रोकने पर सहमत हुए। लेकिन उसके बाद जब भारत ने कहा कि पहलगाम हमले के लिए सिर्फ़ पाकिस्तानी आतंकवादी समूह रेजिस्टेंस फ्रंट ही ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि 'पाकिस्तान' भी उत्तरदायी है दृ जबकि उस वक्त ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को हलाल लंच देने के लिए व्हाइट हाउस में अगवानी की तैयारियां कर रहे थे। अमेरिकी इसे हल्के में नहीं लेने वाले थे।

उसके बाद से अमेरिका ने अपने वक्तव्यों में 'सीमा पारीय आतंकवाद' की निंदा करने और यहां तक कि टीआरएफ को एक आतंकवादी समूह बताकर, एक बहुत सूक्ष्म, किंतु स्पष्ट, बदलाव लाया - लेकिन पाकिस्तान को कभी भी पहलगाम का प्रत्यक्ष मास्टरमाइंड नहीं बताया। शेष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी यही किया है।

पिछले सप्ताह बड़ा परिवर्तन आया। भारतीय नेतृत्व उम्मीद कर रहा है कि भारत-अमेरिका संबंध जल्द स्थिर हो जाएं, लेकिन यह सफर लंबा होगा। आत्म-निरीक्षण करना हो, तो मोदी सरकार को खुद से यह सवाल ज़रूर पूछे कि कूटनीति में पाकिस्तान ने भारत को कैसे पछाड़ा- जबकि वह एक आतंकवाद ग्रस्त देश है, उसकी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है, एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है और मौजूदा प्रधानमंत्री अपनी ही सेना से बेहद डरे हुए हैं। शायद इन मानसूनी सुबहों में इस ईमानदार सवाल का कुछ जवाब मिल जाए।

# धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम जिले के बिरमावल गांव में रविवार रात करीब 11 बजे पंचायत भवन के सामने स्थित बड़केश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़कर खंडित करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने लाठी से मां पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियों को तोड़ दिया और त्रिशूल व शिवलिंग पर लगे तांबे के नाग को भी नुकसान पहुंचाया।

मूर्तियां तोड़े जाने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर पर जमा हो गए और आरोपित को पकड़ लिया। सूचना पर बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 50 वर्षीय आरोपित राधेश्याम मालवीय को हिरासत में ले लिया। ग्रामीण रात 1 बजे तक बिरमावल पुलिस चौकी पर डटे रहे और नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया।

### तीन प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त, प्रकरण दर्ज

घटना के विरोध में ग्रामीण रात 1 बजे बिलपांक थाना पहुंचे और आरोपित राधेश्याम के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। सावन माह के आखिरी सोमवार को सामूहिक रुद्राभिषेक होना था, लेकिन उससे पहले ही मूर्तियां खंडित कर दी गईं। मंदिर में शिव परिवार की कुल पांच मूर्तियां थीं।

इनमें मां पार्वती और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां लाठी से गिराकर तोड़ दी गई, जबकि नंदी की मूर्ति के सिर पर वार करने से एक सींग टूट गया। त्रिशूल और शिवलिंग पर लगाया गया तांबे का नाग भी क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि पुलिस के अनुसार आरोपित राधेश्याम मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है।

### हरियाणा के रामपाल का अनुयायी होने का लगाया आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राधेश्याम, हरियाणा के रामपाल महाराज का अनुयायी है और घटना के समय मूर्तियों पर लगातार लाठी चला रहा था। जब ग्रामीणों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उल्टा उनसे विवाद करने लगा। काफी मशक्कत के बाद उसे काबू किया गया।

चौकी पर गांव के सरपंच प्रतिनिधि रमेश डिंडोर, उपसरपंच महेश्वरसिंह सहित अर्पित जैन, विकास पिपाड़ा, उमेश पाटीदार, धनंजय पाटीदार, कान्हा पाटीदार, राजेंद्र सिंह दरबार, राहुल रावल, गणेश सोनी और प्रमोद गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण देर रात तक मौजूद रहे।

### नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है

मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपित को हिरासत में लिया गया है। पुजारी व ग्रामीणों से चर्चा कर मंदिर में विधि विधान से नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है, हालांकि वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्षतिग्रस्त मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है। अयूब खान, बिलपांक थाना प्रभारी

# सरकारी जमीन निजी लोगों के नाम चढ़ाने के मामले ने पकड़ा तूल

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में सरकारी जमीन निजी लोगों के नाम चढ़ाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ड्रोन सर्वे के दौरान सरकारी आबादी भूमि निजी लोगों के नाम खसरे में चढ़ाने। पंचायत स्तर से कुछ निजी भूखंड व मकानों के बटांकन कर उनकी खरीदी-बिक्री में सहयोग करने संबंधी मामले की जांच को 7 महीने हो चुके है।

जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी से नाराज होकर शिकायतकर्ता पंच गौरव जैन, भाजपा नेता सुरेश धाकड़ ने सोमवार से ग्राम पंचायत प्रांगण में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया।

मामले की शिकायत के बाद जब विभागीय जांच हुई तो तत्कालीन और वर्तमान पंचायत सचिवों को शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी, कूटरचना और धोखाधड़ी का जिम्मेदार पाया था। ये रिपोर्ट 5 फरवरी को आई लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैन ने बताया हमने सभी कानूनी और प्रशासनिक रास्ते अपनाए। पुलिस को आवेदन दिए। उच्चाधिकारियों को डाक से शिकायतें भेजीं। कोई नतीजा नहीं निकला। हमारी इस लड़ाई में न्याय के इंतजार में एक शिकायतकर्ता बाबूलाल बामता का तो निधन हो गया। अब अनशन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है इसलिए ये शुरुआत की।

### धरना स्थल पर शाम को किया गया सुंदरकांड पाठ

अनशन के समर्थन में धरनास्थल पर शाम को सुंदरकांड पाठ भी किया। इसमें ग्रामीणजन शामिल हुए। अनशन कर रहे जैन व धाकड़ ने कहा कि दोषी सचिवों के खिलाफ एफआईआर, सचिव घनश्याम सूर्यवंशी को निलंबित करने और फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले अन्य दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होने तक अनशन जारी रहेगा।

# नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले गया था रेहान

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले से क्राइम का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिले के नयापुरा निवासी 19 वर्षीय युवक रेहान मेव ने इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर ली। 8 माह की दोस्ती के बाद मंगलवार को युवक स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रा पर दबाव बनाकर यूनिफॉर्म में ही बाइक से सुनसान खदान की ओर ले गया।

वहां संदेह होने पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और थाने ले गए। मौके पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

नयापुरा निवासी रेहान पिता रईस मेव ने दलौदा के निजी स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। मंगलवार को युवक बाइक से दलौदा पहुंचा और स्कूल की छुट्टी के बाद उसे बाइक पर बैठाकर एलची रोड की ओर स्थित सुनसान खदान के पास ले गया। छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर संदेह होने पर कुछ लोगों ने युवक को रोका और पूछताछ की।

सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और नाबालिग छात्रा और युवक को दलौदा थाने ले जाया गया। थाने पर छात्रा के परिजन और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और विरोध जताया। साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और नगर में जुलूस निकालने की मांग की। इस दौरान में दलौदा हाइवे कुछ देर के लिए जाम करने का प्रयास भी किया। इस बीच एक पेट्रोल टैंकर और यात्री बस की टक्कर भी हो गई।

हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी, मंदसौर ग्रामीण एसडीओपी कीर्ति बघेल सहित क्षेत्र के अन्य 4 थानों से भी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर मामला शांत कराया। मंदसौर ग्रामीण एसडीओपी बघेल ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर युवक रेहान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धारा में केस दर्ज कर लिया है। मामले में जांच की जा रही है।

# आंगनवाड़ी केंद्र में जागरूकता शिविर का आयोजन

माही की गूंज, शाजापुर।

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में स्तनपान सप्ताह की गतिविधियों के तहत ग्राम लाहौरी के आंगनवाड़ी केंद्र में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें स्वास्थ्य संबंधी गतिविधिया जैसे बच्चों का टीकाकरण विटामिन ÷ए÷ की खुराक बच्चों को पीलवाई गई और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया।

महिला एवं बाल विकास सहायक संचालक सुश्री नीलम चौहान ने महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण की चर्चा करते हुए कहा कि, बच्चों को सही तरीके से स्तनपान करवाने में दादी-नानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली बार माँ बनने वाली माताओं को समझाईश अवश्य दें। इस दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एवं अन्य अपराधों से बचाव के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन एवं हबफॉर वुमन एम्पावरमेंट के साथ ही वन स्टॉप सेंटर की जानकारी दी। लाडली लक्ष्मी योजना व प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के हितग्राहियों के खाते को डीबीटी व आधार से लिंक करवाने तथा एफआरएस करवाने की समझाईश दी। साथ ही वजन लिये गए बच्चों का क्रॉस सत्यापन किया गया।

इस दौरान पर्यवेक्षक श्रीमती प्रिया गोस्वामी ने महिलाओ को समझाईश देते हुए कहा की बच्चें के जन्म के तुरंत बाद माँ का गाढा दूध नवजात शिशु को पिलाए। जन्म के तुरंत बाद का दूध बच्चो का टिका होता है, जो विभिन्न बीमारियों से रोकथाम करता हैं। साथ ही 1000 दिवस बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एएनएम रत्ना व्यास ने बच्चों व महिलाओं का स्वास्थ्य परिक्षण किया। पर्यवेक्षक श्रीमती संगीता यादव के नेतृत्व में आंगनवाड़ी केंद्र पर स्तनपान सप्ताह के बारे में महिलाओ को जानकरी दी व वृक्षारोपण करवाया। स्तनपान के बारे में भ्रांतिया दूर करने के लिए आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा नारे लेखन कर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा हैं।

## घोड़ारोज की टक्कर से दंपति गंभीर घायल

माही की गूंज, मंदसौर। जिले के करनाखेड़ी-राकोदा रोड पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में नंदावता निवासी एक दंपति तेज रफ्तार घोड़ारोज की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उनकी नाजुक हालत को देखते हुए अहमदाबाद रेफर किया गया है। क्षेत्र में लंबे समय से बेकाबू रोजड़ों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है इससे पहले भी करजू गांव का एक युवक इसी तरह की दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था और वह आज भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

वर्तमान मंदसौर विधायक विपिन जैन ने भी इस विषय को गंभीरता से विधानसभा में उठाया था और क्षेत्र में बेकाबू रोजड़ों से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताई थी। उन्होंने शासन से मांग की थी कि इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि सड़क मार्गों पर घूम रहे इन बेकाबू रोजड़ों को नियंत्रित करने के लिए तुरंत विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से आम नागरिकों की जान बचाई जा सके।

## हर्षोल्लास से मनाया जायेगा स्वतंत्रता दिवस समारोह

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के लिए कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक कर कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाने के लिए जरूरी तैयारियों पूरी करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि, मुख्य समारोह पीजी कॉलेज ग्राउंड पर 15 अगस्त को प्रातः 9 बजे से आयोजित होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की 13 अगस्त को पीजी कॉलेज ग्राउंड में फाइनल रिहर्सल की जाएगी। जिसमें सभी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। 15 अगस्त के दिन मुख्य कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को लाने व वापस घर छोड़ने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। बच्चों का विशेष तौर पर ख्याल रखें। सभी कार्यालयों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर 14 एवं 15 अगस्त 2025 को रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों एवं लोकतंत्र सेनानियों को कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया जाये। वृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शाल, श्रीफल से सम्मानित किया जाये।

सभी शासकीय भवनों पर विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख द्वारा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण व राष्ट्र गान का आयोजन किया जाए। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, एडिशनल एसपी बघेल, सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

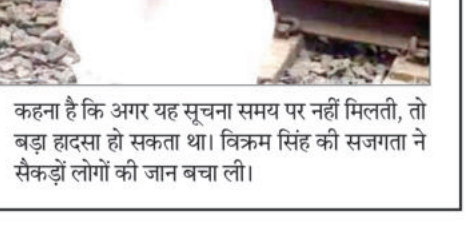

# ड्यूटी के दौरान नर्सों को मेहंदी लगाना पड़ा भारी, वार्ड से हटाया

माही की गूंज, मंदसौर।

जिला अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड में ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनकर मेहंदी लगाने वाली दो स्टाफ नर्सों पर सिविल सर्जन ने कार्रवाई की है। दोनों स्टाफ नर्स को अब एनएससीयू वार्ड में ड्यूटी पर भेज दिया है।

दरअसल, मेटरनिटी वार्ड में यूनिफॉर्म पहने दो स्टाफ नर्स का मेहंदी लगाते हुए वीडियो सामने आया था। इस पर सिविल सर्जन डॉ. बीएल रावत ने संज्ञान लेते हुए स्टाफ नर्स चंदा कुमावत और प्रियंका डांगी के साथ प्रभारी सेरमा जॉनसन को भी नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा था। स्टाफ नर्सों ने जवाब में बताया कि उनकी ड्यूटी समाप्त हो चुकी थी और उन्हें एक कार्यक्रम में जाना था इसलिए मेहंदी लगाई।

हालांकि, सिविल सर्जन ने दोनों नर्सों को मेटरनिटी वार्ड से हटाकर एसएनसीयू (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) में ड्यूटी पर लगाया गया है। सिविल सर्जन रावत ने बताया कि प्रभारी सेरमा जॉनसन का जवाब अब तक नहीं मिला है, उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

# एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर बचा ली यात्रियों की जान

माही की गूंज, रतलाम।

**दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर मंगलवार सुबह बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया, जब 66 वर्षीय वृद्ध किसान ने रेलवे ट्रैक पर दरार देखी और लगभग आधा किलोमीटर दौड़ते हुए लूनी रिछा स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को जानकारी दी। उनकी सजगता से ट्रेनों का आवागमन समय रहते रोका गया।**

स्टेशन अधीक्षक इरफान अली ने बताया कि, सुबह करीब 7:46 बजे रिछा गांव निवासी 66 वर्षीय किसान विक्रम सिंह खेत पर जा रहे थे, तभी अपलाइन ट्रैक में उन्हें काफी दरार नजर आई। उन्होंने कोई देरी नहीं की और भागते हुए स्टेशन पहुंचे।

वहां मौजूद प्वाइंट मैन निलेश गुर्जर को पूरी बात बताई और दोनों तत्काल स्टेशन अधीक्षक के पास पहुंचे। किसान विक्रम सिंह ने बताया कि मैं रोज की तरह खेत पर जा रहा था, लेकिन आज जैसे ही ट्रैक पार करने लगा, तो कुछ अलग सा नजर आया।

पास जाकर देखा तो पटरी में सीधी दरार थी। मैं घबराया नहीं और सूचना देने के लिए दौड़ पड़ा। स्टेशन अधीक्षक ने तत्काल प्वाइंटमैन को भेजा और दरार की पुष्टि होते ही रेल यातायात तत्काल बंद करवा दिया गया।

### ट्रेन आने वाली थी

कुछ समय बाद ही डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस (20156) दिल्ली की ओर से आने वाली थी, जिसे समय रहते रोक लिया गया। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। करीब आधे घंटे तक इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। पहले अस्थायी मरम्मत कर ट्रेनों को धीमी गति से निकाला गया और फिर करीब तीन घंटे की तकनीकी मरम्मत के बाद ट्रैक को पूरी तरह सुचारू किया गया।

### रेलवे ने किया सम्मानित

किसान की साहसिक सतर्कता की जानकारी जब कोटा रेल मंडल तक पहुंची, तो अपर मंडल रेल प्रबंधक ने विक्रम सिंह को 2100 रुपये की पुरस्कार राशि देने के निर्देश दिए। स्टेशन अधीक्षक द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र और राशि देकर सम्मानित किया गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगर यह सूचना समय पर नहीं मिलती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। विक्रम सिंह की सजगता ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली।

# कोर्ट के आदेश पर एनएचडीसी की संपत्ति कुर्क

**माही की गूंजए खंडवा।**

खंडवा जिला न्यायालय के आदेश के बाद एनएचडीसी ;नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट निगमद्ध की संपत्ति कुर्क की गई। इस दौरान 28 इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त की गईए जिनमें छायाप्रति मशीनए केन्द्रीय प्रक्रमक इकाई ;सीपीयूद्ध आदि शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में सामान जब्त कर वाहन में भरकर न्यायालय ले जाया गया।

डूब प्रभावितों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्राणेंद्र रांका ने बताया कि इंदिरा सागर बांध से प्रभावित किसानों को न्यायालय द्वारा पारित अवॉर्ड के बाद भी उचित मुआवजा नहीं दिया गया। देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र के 36 किसान ऐसे हैंए जिन्हें मुआवजा और ब्याज मिलाकर लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि मिलनी थी।

फिलहाल एक किसान दशरथ पिता नू को 48 लाख रुपये की अवॉर्ड राशि को लेकर कार्रवाई की गई है। विभाग ने बार.बार समय माँगाए लेकिन भुगतान नहीं किया गया।

रांका ने बताया कि खातेगांव न्यायालय ने 2017 में प्रभावित किसानों की याचिका पर निर्णय दिया था। बाद में प्रकरण खंडवा जिला न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गयाए क्योंकि एनएचडीसी का मुख्यालय खंडवा में स्थित है।

खंडवा कोर्ट ने 24 जून 2025 को आदेश पारित करते हुए रोहनिया गांव के किसान दशरथ के पक्ष में निर्णय दियाए जिसमें 2017 के अवॉर्ड के अनुसार ब्याज सहित राशि देने को कहा गया।

इस निर्णय के खिलाफ एनएचडीसी ने उच्च न्यायालयए इंदौर में अपील की थी। इंदौर उच्च न्यायालय ने हाल ही में याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद खंडवा कोर्ट ने संपत्ति कुर्की के लिए वारंट जारी किया।

बुधवार को न्यायालय के प्रतिनिधि विभागीय कार्यालय पहुँचे और नोटिस थमाया। एनएचडीसी अधिकारियों ने नोटिस लेने से इनकार कर दियाए जिसके बाद न्यायालय के मुंशी ने नोटिस आवक. जावक शाखा में दर्ज करवा दिया और सामग्री को जब्त कर वाहन में भरकर न्यायालय पहुँचाया गया।

एनएचडीसी की ओर से अधिवक्ता सुनीता खेवारे ने कहा कि यह कार्रवाई पूर्व के मामलों में की गई कुर्की की पुनरावृत्ति है। हमने उच्च न्यायालय में अपील की थीए जो खारिज हो गई। अब हम इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे।

## सूत मिल के अंशधारकों का विरोध

**माही की गूंज, खरगोन।**

जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल के लगभग 200 अंशधारकों ने मिल के संचालन मंडल के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को सभी अंशधारक कलेक्टर भव्या मित्तल से मिले और उन्हें आवेदन देकर संचालन मंडल पर सहकारिता नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए।

अंशधारकों ने माँग की है कि मिल में हुए आर्थिक लेन-देन की जाँच करवाई जाएए संचालन मंडल को भंग किया जाए और दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। इस दौरान नाराज़ अंशधारकों ने 'संचालन मंडल को भंग करो' जैसे नारे भी लगाए।

अंशधारकों में शामिल मदन यादव, जगन्नाथ पटेल, माधव पटेल, दुर्गेश पंवार और जयराम पटेल ने बताया कि मिल दिसम्बर 2023 से बंद है, फिर भी नियमों को दरकिनार कर संचालन मंडल का चुनाव कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से संचालन मंडल मनमर्जी से मिल चला रहा है। अंशधारकों को न तो किसी बैठक में बुलाया जाता है, न ही चुनाव और वार्षिक आमसभा की जानकारी दी जाती है।

अंशधारकों ने यह भी सवाल उठाया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूत मिल को 25.56 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, फिर अचानक घाटा कैसे हो गया? इसकी भी जाँच की माँग की गई है। वहीं पूरे मामले पर उप कलेक्टर पूर्व मंडलोई ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।

## चाय स्टॉल पर गैस सिलेंडर में लगी आग, बड़ा हादसा टला

**माही की गूंज, खरगोन।** वार्ड क्रमांक 12 स्थित हैदर मस्तान चौक क्षेत्र में मंगलवार रात एक चाय-नाश्ते की ठेली पर गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई। दुकानदारों ने तत्परता दिखाते हुए लगभग 20 से 25 दुकानों के शटर तुरंत नीचे कर दिए और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। करीब 15 मिनट तक गैस सिलेंडर आग की चपेट में रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद नासिर अपने चाय-नाश्ते के ठेले पर आलूबड़े तल रहे थे, तभी रात लगभग साढ़े 9 बजे गैस पाइप से रिसाव शुरू हुआ और चिंगारी सिलेंडर तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग भड़क गई और सिलेंडर जलती हुई आग के गोले में तब्दील हो गया। यह देख आसपास के दुकानदार घबरा गए। स्थानीय पार्षद रियाज शेख ने मौके पर पहुंचकर नागरिकों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने गीले बोरे और मटकों में पानी भरकर आग पर डाला। इसी बीच अग्निशमन केंद्र को सूचना दी गई, जिसके बाद लगभग 7 मिनट में दमकल वाहन मौके पर पहुंच गया।

## राजस्व अधिकारियों ने किया कार्य बहिष्कार

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी जिले में राजस्व अधिकारियों ने न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्यों के बंटवारे के विरोध में बुधवार से कार्य का बहिष्कार प्रारंभ कर दिया है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार अब केवल आपदा प्रबंधन का कार्य ही करेंगे। वे मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगेए लेकिन सामूहिक हड़ताल पर नहीं जाएंगे।

इस विरोध का कारण तहसीलों में अधिकारियों के कार्यों का न्यायिक और गैर-न्यायिक रूप में पृथक्करण है। न्यायिक कार्य देखने वाले अधिकारी अब फील्ड में नहीं जा रहे, वहीं जो अधिकारी फील्ड में तैनात हैं, वे न्यायिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के मनीष पांडे ने बताया कि इस व्यवस्था को लेकर पूर्व में राजस्व मंत्री करण वर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। उस समय यह कहा गया था कि यह व्यवस्था केवल तीन माह के लिए बारह जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में लागू की जाएगी। लेकिन बाद में इसे अन्य जिलों में भी लागू कर दिया गया।

इसी निर्णय के विरोध में संघ के जिला अध्यक्षों और प्रतिनिधियों की बैठक में 16 अगस्त से कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया। राजस्व अधिकारी अपने विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट कर रहे हैं।

इस कार्य बहिष्कार का सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। नामांतरणए सीमांकनए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फसल क्षति का आवेदन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य ठप हो गए हैं। बड़वानी जिले के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने बुधवार को राजस्व कार्यों के लिए प्राप्त सरकारी डोंगल और वाहन भी वापस कर दिए हैं।

## कुएं में डूबने से कॉलेज छात्र की मौत

**माही की गूंज, खंडवा।**

जिले में एक 18 वर्षीय युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतक कॉलेज के प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था। हाल ही में उसने शहर के एसएन महाविद्यालय में प्रवेश लिया था और इन दिनों घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मंगलवार दोपहर वह खेत में अपने पिता को चाय और नाश्ता देने गया था।

पिता के सामने ही वह वापस घर के लिए रवाना हुआए लेकिन घर नहीं पहुँचा। देर रात तक उसके नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की। बुधवार सुबह खेत के कुएं के पास उसकी चप्पलें दिखाई दीं। संदेह होने पर कुएं में देखा गया तो उसका शव बरामद हुआ।

यह घटना मोघट रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया तहार की है। कुएं में शव मिलने की सूचना पर रामेश्वर पुलिस चौकी से पुलिस मौके पर पहुँची। शव की पहचान कृष्णा पिता पवन राजपूत ;18 वर्षद्ध के रूप में हुई। मृतक का मौसेरा भाई कपिल राजपूत ने बताया कि वह पढ़ाई में तेज़ और सरल स्वभाव का था।

मंगलवार को दोपहर पिता ने उसे खेत पर खाने और चाय के लिए बुलाया था। वह खेत गया और लौटते समय पिता के सामने ही घर की ओर रवाना हुआ थाए परंतु घर नहीं पहुँचा। रातभर उसकी तलाश की गईए फिर खेत जाकर देखा गया तो कुएं के पास उसकी चप्पलें पड़ी थीं।

कृष्णा हाल ही में बारहवीं कक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर चर्चा में आया था। सरकार से उसे लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हज़ार रुपये की सहायता भी मिली थी। परिवार में वह इकलौता पुत्र था। उसकी असमय मृत्यु से पूरे गाँव में शोक का माहौल है।

रामेश्वर चौकी प्रभारी सुभाष नावड़ेका ने बताया कि कृष्णा के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। परिजनों के अनुसार वह दोपहर को खेत से निकल गया था और पिता खेत पर शाम को पहुँचे थे। ऐसे में घटना का समय स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

## सुसाइड नोट में उपसरपंच का नाम, फिर भी नहीं हो रही कार्रवाई

**माही की गूंज, बड़वानी।**

बोरलाय गाँव में मूलचंद यादव नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बुधवार को इस मामले में मृतक के परिजन पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर से मिले और उन्हें एक शिकायती आवेदन सौंपा।

मृतक की बेटियाँ सोनूए राजेश्वरी और लक्ष्मी ने बताया कि उनके पिता ने एक आत्महत्या पत्र छोड़ा हैए जिसमें गाँव के कुछ लोगों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे गए हैंए लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बेटी लक्ष्मी ने कहा कि उनके पिता लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। आठ दिन पहले उन्होंने अंजड़ थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थीए लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

मृतक के दामाद दिनेश यादव ने कहा कि कुछ स्थानीय लोगों ने उनके ससुर को लगातार प्रताड़ित कियाए जिसकी वजह से उन्होंने 24 जुलाई को बोरलाय गाँव में फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या पत्र में ग्राम पंचायत उपसरपंच गणेश यादव और घनश्याम उर्फघमंडी यादव पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम कराया गया है और अब तक 33 गवाहों के बयान लिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच चल रही हैए लेकिन परिजनों का आरोप है कि अब तक किसी के खिलाफकोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

## जाहिर सुचना

यह कि, मेरे पक्षकार श्री नविनचंद्रसिंह पिता स्व. गजराजसिंह जी राठौर एवं श्रीमती पदमीलासिंह पति नविनचंद्रसिह राठोर निवासीगण-ग्राम बोडायता तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. के द्वारा कृषक श्री रणजीतसिंह पिता मनोहरसिंह जी राठौर निवासी सारंगी तहसील पेटलावद जिला झाबुआ के स्वामित्व मालकी वाली कृषि भूमि पटवारी हल्का नम्बर 24 सर्वे नम्बर 1715/3 व 1717/4 कुल सर्वे नम्बर 02, कुल रकबा 1.06, कुल लगान 8.27 पैसे की कृषि भूमि रूपयें 15,00,000/- पन्द्रह लाख में क्रय कर ली है, तथा विक्रेता के द्वारा मेरे पक्षकारगण के पक्ष में विधिवत विक्रय अनुबंध भी दिनांक 24.11.2022 कों निष्पादित कर सदर भूमि का रिक्त आधिपत्य भी मेरे पक्षकारगण को सौप दिया है। तदनुसार मेरे पक्षकारगण का शांतिप्रिय आधिपत्य चला आ रहा है। मेरे पक्षकारगण के द्वारा समस्त प्रतिफल की अदायगी भी विक्रेता कों कर दी गई हैं। किन्तु विक्रेता द्वारा मेरे पक्षकारगण के पक्ष में अभी तक ई पंजीयन निष्पादित नही करवाया है।

यह कि, सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि उपरोक्त क्रय सुदा भूमि के सम्बंध में मेरे पक्षकारगण के बाले बाल किसी भी प्रकार का पश्चावर्तीय सौदा, अंतरण, गिरवी, बक्सिस, दान, नामातरणं आदि की कार्यवाही कृषक रणजीतसिंह राठौर के साथ नही करे, अन्यथा ऐसा कोई भी संव्यवहार अवैध स्वरूप का होकर मेरे पक्षकारगण पर बंधनकारक नही रहेगा।

अतः जाहिर सुचना का प्रकाशन मेरे पक्षकारगण की ओर सें किया जाता है सौ सही है।

07.08 2025 पेटलावद

एडवोकेट
राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी
पेटलावद जिला झाबुआ

# पंजाब में चिंता बढ़ाते भूजल संकट के संकेत

पंजाब के सामने बहुत भारी भूजल संकट मुंह बाये खड़ा है, जिससे इसकी सभ्यता की सततता को ही खतरा बन चला है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में उपयोग करने योग्य भूजल की आखिरी बूंद भी अगले 14 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। वर्तमान राजनीतिक कार्यपालिका, योजनाकारों और नागरिक समाज का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि भूजल न केवल दुनिया के इस क्षेत्र की वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी कायम रहे।

वैज्ञानिक डाटा से पता चलता है कि पंजाब हर साल धरती के गर्भ से 28 मिलियन एकड़ फुट पानी निकाल रहा है, जबकि वर्षा और इसकी तीन बारहमासी नदियों के माध्यम से भरपाई केवल 17 मिलियन एकड़ फुट की हो पाती है। इस असंतुलन के कारण भूजल स्तर प्रति वर्ष लगभग आधा मीटर की खतरनाक दर से और नीचे गिरता जा रहा है, जिसके चलते पंजाब रेगिस्तान बनने के करीब है।

इस अत्यधिक दोहन के सबसे मुख्य कारणों में से एक है पंजाब में 'ऊर्जा-पानी-खाद्य' रूपी दुष्चक्र। चूंकि सरकार किसानों को अनाज उगाने के वास्ते पानी निकालने के लिए मुफ्त में पॉवर उपलब्ध कराती है, खासकर धान के लिए, इसलिए इससे पहले कि पंजाब बंजर और नकारा भूमि में तब्दील हो जाए,इस संकट को दूर करने को व्यावहारिक उपाय करना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है। इसके अलावा, यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि न केवल भूजल बहुत तेजी से गिर रहा है, बल्कि धरती की गहरी परतों से निकाले जा रहे पानी में भारी धातुएं और नाइट्रेट की मात्रा भी खतरनाक स्तर की होती है, जो इसे मनुष्यों और जानवरों के इस्तेमाल के अनुपयुक्त बनाते हैं। इसलिए, सही समय है कि सरकार स्थिति सुधारने के लिए तत्काल और जरूरी उपाय करे।

वैज्ञानिक मानसून के आगमन के साथ धान की रोपाई करने की सलाह देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार को 20 जून से चरणबद्ध रोपाई कार्यक्रम लागू करवाना चाहिए। इसकी कई वजहें हैं जैसे किसान अब मुख्यतः कम अवधि वाली धान की किस्मों की खेती कर रहे हैं, जो 90-100 दिन में पककर तैयार होती हैं, जबकि 2009 से पहले लंबी अवधि वाली किस्मों की खेती की जाती थी, जो 130-140 दिन में तैयार होती थी। वहीं पंजाब देश का पहला राज्य था, जिसने 2008 में भूजल बचाने और संरक्षित करने के उद्देश्य से धान बुआई की तिथि विनियमित करने के लिए प्रगतिशील कानून बनाया था जिसके तहत धान रोपाई की तिथि 10 जून तय की गई थी, जिसे 2014 में आगे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया और तबसे तिथियों में मामूली हेरफेर के साथ यह तारीख जारी है।

पिछले 17 वर्षों में किसान अपनी खरीफ फसलों के उत्पादन का 'पंजाब भू-मृदा जल संरक्षण अधिनियम 2009' नामक इस कानून के मुताबिक समायोजन करके करते आए हैं। पंजाब कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 2009 से पहले भूजल स्तर में वार्षिक गिरावट 75 सेमी. थी, जो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण बाद वाली अवधि में घटकर 40 सेमी. रह गई।

रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब के तीनों जलाशयों - भाखड़ा बांध, रणजीत सागर बांध और पोंग बांध - में जल स्तर पिछले वर्षों की तुलना में सामान्य से 52 फीसदी कम रहा। पंजाब को धान की खेती के लिए प्रमुख तौर पर इन जलाशयों से लगभग 14.50 एमएएफ पानी मिलता है। इस बार गर्मी के मौसम में सिंचाई के लिए नहरी पानी कम उपलब्ध होने के अनुमान थे, ऐसे में धान की फसल के लिए भूजल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। एक किलो धान पैदा करने के लिए लगभग 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए किसान नहरी पानी की आपूर्ति में कमी को भूजल निकालकर पूरा करता है। सामान्य से अधिक तापमान और लू लंबी चलने का पूर्वानुमान हो, तो जून या उससे पहले रोपे गए धान को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अतएव धान की रोपाई को जून के आखिरी सप्ताह (मानसून के आगमन के करीब तक) टालना बेहतर है।

जून के अंत में रोपा गया धान अक्तूबर की शुरुआत में पक जाता है, इस समय कटाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। जबकि अगेती रोपाई करने से सितंबर के महीने में, मानसून के अंतिम चरण में, कटाई करनी पड़ती है, जिससे धान के दाने बारिश, तेज़ हवाओं और उच्च आर्द्रता के संपर्क में आते हैं। परिणामस्वरूप किसानों को नमी युक्त धान बेचने संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे भी केंद्र सरकार ने धान खरीद का संचालन एक अक्तूबर से ही अनिवार्य कर दिया है।

दरअसल, पूसा 44 किस्म और इसकी विभिन्न वैरायटी (पीली पूसा और डोगर पूसा) न केवल अपनी लंबी अवधि के कारण पानी की अधिक खपत करती हैं, बल्कि भारी मात्रा में पराली पैदा करने के कारण प्रदूषण भी बढ़ाने वाली हैं। पंजाब सरकार को किसानों को पहले से सलाह देकर और राज्य खरीद एजेंसियों को उपरोक्त किस्म के अनाज की खरीद न करने का निर्देश देकर इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

पंजाब हर साल अपनी रिचार्ज जल राशि से लगभग 11 एमएएफ अधिक भूजल निकाल रहा है, जिसकी गैरटिकाऊ निकासी दर 165 फीसदी है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुरक्षित सीमा 75 प्रतिशत है। इसलिए, राज्य को मानक निकासी दर से अधिक निकाले जल की पुनःपूर्ति बढ़ाने के लिए व्यापक भूजल पुनर्भरण नीति तैयार और लागू करनी चाहिए। सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी के साथ कृत्रिम व प्राकृतिक पुनर्भरण तकनीकों के संयोजन को लागू करना चाहिए।

फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए। पंजाब में खरीफ सीजन में कभी कपास और मक्का प्रमुख फसलें होती थीं। हालांकि, इन फसलों के प्रतिकूल उत्पादन और खरीद व्यवस्था ने किसानों को धान की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया, जिसके उत्पादन में जोखिम न केवल कम है, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी में उठाए जाने की भी गारंटी है। नतीजतन, धान के तहत रकबा 1990 में 50 लाख एकड़ से बढ़कर पिछले साल 80 लाख एकड़ हो गया, जिससे भूजल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। बीस लाख एकड़ पर वैकल्पिक खरीफ फसलों को प्रोत्साहित करने से भूजल संतुलन काफी हद तक बहाल किया जा सकता है। शुरुआत में सरकार को उन 11 ब्लॉकों में वैकल्पिक फसलों को अनिवार्य करना चाहिए जहां भूजल निकासी मात्रा रिचार्ज दर की बनिस्बत 300 फीसदी के भयावह स्तर से अधिक है।

कहन सिंह पन्नू

पंजाब में खेती एक चौराहे पर है। कृषि के लिए आवंटित 14524 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के बावजूद, इस क्षेत्र की पीड़ाएं कम नहीं हुईं, और भूजल संकट लगातार बदतर हो रहा है। तत्काल नीतिगत बदलाव और ठोस कार्रवाई के बिना पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिरता गंभीरतम खतरे में है। कार्रवाई करने का समय तुरंत और इसी पल से है।

# पूर्व सिविल सर्जन डॉ. वर्मा और अन्य पर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज

माही की गूंज, उज्जैन।

**जिले के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. पी एन वर्मा और अन्य दो पर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हुआ है। खरीदी मामले में शासन को आर्थिक हानि आदि का आरोप है।**

लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि, धर्मेंद्र शर्मा निवासी ग्राम नजरपुर, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन ने लोकायुक्त उज्जैन में पुलिस अधीक्षक के समक्ष शासकीय चरक भवन अस्पताल के संचालन के लिए समय-समय पर वस्तुओं एवं सेवाओं का नियम विरूद्ध तरीके से क्रय किये जाने के संबंध में शिकायत की थी।

उक्त शिकायत की जॉच इस इकाई में पदस्थ डीएसपी राजेश पाठक द्वारा की गई। प्रकरण की जॉच पर यह पाया गया कि, जिन फर्मों को दो वर्ष के लिए निविदा कर कार्यादेश दिया गया था, उनकी दो वर्षो की निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात लगभग दो से तीन वर्ष तक बिना नई निविदा के पुरानी फर्मो डेहली रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडिशनिंग इंजिनियरिंग, इन्दौर एवं रिडेन एस.पी. सी. ऑक्सीजन गैस सप्लायर को जिला उज्जैन से ही कार्य करवाया जाकर उक्त फर्मों को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया गया तथा बिना प्रतिस्पर्धा की निविदा मूल्य से कार्य करवाये जाने के कारण शासन को अर्थिक क्षति हुई है।

यह उल्लेखनीय है की विभिन्न फर्मों को क्रय, कार्य के भुगतान के समय जी. एस. टी राशि का भुगतान भी किया गया था, जिसे संबंधित फर्मों द्वारा शासन पक्ष में जमा नही करवाया गया। इसके बावजूद बिना क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के नियम विरूद्ध रूप से पश्चातवर्ती भुगतान भी किया गया । तत्कालीन सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय उज्जैन, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक उज्जैन (वर्तमान में सेवानिवृत्त) प्रदत्त वित्तीय शक्तियो के विपरीत, फर्मों को अत्याधिक राशि का भुगतान, बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रकरण में किये गये अनियमित भुगतान की कुल राशि का निर्धारण विवेचना के दौरान भुगतान का ऑडिट करवाकर किया जावेगा।

इस प्रकार निम्नलिखित आरोपी लोकसेवकों द्वारा पदीय कदाचरण करते हुऐं विभिन्न फर्मों के संचालको से मिलकर, आपराधिक षडयंत्रपूर्वक प्रदत वित्तीय शक्तियों के विपरीत जाकर शासकीय राशि का नियमविरूद्ध भुगतान किया गया, जिससे शासन का आर्थिक हानि हुई ।

अतः कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक में पदस्थ तत्कालीन सिविल सर्जन 1 - डॉ. प्रयागनारायण वर्मा (हाल - सेवानिवृत्त), 2- तत्कालीन लेखापाल राजकुमार सोनी (हाल - सेवानिवृत्त) एवं 3 - तत्कालीन प्रभारी लिपिक राहुल पण्ड्या, (मूल पद ड्रेसर) ग्रेड-1 प्रभारी लिपिक के विरूद्ध धारा 7 - सी 13 (1) ए, 13 (2) भ्र.नि.अधि 1988 (संशोधन 2018) एवं भा.द.वि. की धारा 120-बी के अंतर्गत क्रमांक 144 / 2025 एफ. आई.आर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

## महिला मंडल ने निकाली कांवड़ यात्रा, त्रिलोकेश्वर महादेव का किया अभिषेक

माही की गूंज, आम्बुआ।

श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना पूजा अर्चना करने का प्रावधान है जिसमें शिवजी को कांवड़ का जल चढ़ाया जाता है। उसी कड़ी में आम्बुआ में भी महिला मंडल द्वारा तथा बाल शिव भक्त मंडल के साथ त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया जाने का समाचार है।

श्रावण मास के अंतिम सप्ताह में शिव भक्तों में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। शिवालयों सुबह से ही भूतनाथ भगवान शिव की पूजा अर्चना का क्रम शुरू हो कर देर रात तक यह सिलसिला जारी रहता है। इसी कड़ी में शिवजी को कांवड़ यात्रा के माध्यम से जल चढ़ाया जाता है। आम्बुआ में भी बाल शिव भक्त मंडल तथा महिला मंडल द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा हथिनेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई जोकि क़स्बे में भ्रमण करते हुए आवास फलिया में नव निर्मित त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची जहां पर गौरा पति औघड़ दानी भोले नाथ का सभी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ जलाभिषेक किया तथा पुजन आरती के बाद शिव जी के मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्य क्रम को सफल बनाने में सभी सनातनी शिव भक्तों का सराहनीय सहयोग रहा।

## प्रधान जिला न्यायाधीश ने जिला जेल का किया औचक निरीक्षण

माही की गूंज, शाजापुर।

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (सालसा) के निर्देशानुसार आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर आनंद कुमार तिवारी के द्वारा जिला जेल शाजापुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा उपस्थित थी।

जेल निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी ने प्रत्येक बैरक में जाकर पुरूष एवं महिला बंदियों को दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया तथा जेलबंदियों से जेल प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं जैसे- भोजन, पेयजल, वस्त्र, मनोरंजन के साधन एवं साफ-सफाई के बारे में चर्चा की। इसके अतिरिक्त जेलबंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी। जेल परिसर में स्थित खाद्यान्न कक्ष का भी निरीक्षण किया, जिसमें रखी हुई खाद्यान्न जैसे-दाल, आटा, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों का अवलोकन किया। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा जेल प्रशासन को जेल में स्थापित शौचालय, स्नानागार, जेल परिसर एवं बैरक की नियमित रूप से साफ-सफाई करने एवं जेल में निरूद्ध जेल बंदियों को दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जेल में उपस्थित महिला बंदियों से भी चर्चा कर उनके लंबित प्रकरणों की स्थिति जानी एवं महिला बैरक में निरूद्ध महिला बंदियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। जेल निरीक्षण के दौरान जेल में 117 पुरूष एवं 08 महिला बंदी निरूद्ध होना पाए गए तथा कोई भी गर्भवती महिला नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान बंदियों ने अपनी समस्याएं प्रधान जिला न्यायाधीश को बताई, जिसका उचित निराकरण करने के लिए संबंधित जेल प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक दुष्यंत कुमार पगारे एवं उप जेल अधीक्षक सुनील मंडलेकर सहित जेल प्रहरीगण मौजूद थे।

## सीएम राईज स्कूल शोकॉज नोटिस को गंभीरता से ले

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में सीएम राइस स्कूल के निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री निधि मिश्रा, प्रभारी सहायक आयुक्त संजय परवाल, सहित सीएम राईज विद्यालय के प्राचार्य, सब इंजीनियर एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर डॉ बेडेकर ने प्रत्येक सीएम राईज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होने निर्देशित किया कि सभी सीएम राईज स्कूलों में साईट डेवलपमेंट के साथ साईट क्लीयरिंग का कार्य भी संपन्न किया जाए ताकि समय की बचत हो। इस दौरान सीएम राईस सोण्डवा के निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि निर्माण से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण हो गए, बाहरी क्षेत्र में एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण शेष है जो कि आगामी माह में पूर्ण हो जाएगा । इस दौरान वीडियो एवं वर्तमान फोटो के माध्यम से निर्माण कार्य की समीक्षा की गई ,निर्माण एजेंसी के द्वारा समय सीमा में कार्य पूर्ण करने एवं अच्छा निर्माण कार्य करने पर कलेक्टर डॉ बेडेकर ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि आगामी 15 अगस्त को संबंधित को सम्मानित किया जाए।

इस दौरान नानीबडोई कट्ठीवाड़ा के समीक्षा के दौरान पाया गया कि संबंधित प्राचार्य अमर सिंह कनेश द्वारा निर्माण कार्य एवं अन्य विषयों पर रूचि न ली जा रही, संबंधित के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर डॉ बेडेकर ने दिए। इस दौरान उन्होंने समस्त निर्माण एजेंसी एवं प्राचार्य और संबंधित इंजीनियर को निर्देशित करते हुए कहा कि, आगामी माह में दोबारा प्रगति की समीक्षा की जाएगी सभी अधिकारी कार्य में गति लाए अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।

## कुबेरेश्वर धाम में 11 किलोमीटर की कावड़ यात्रा

**सीहोर।** सीहोर की सड़कों पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 6 अगस्त को आयोजित होने वाली कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचे। श्रद्धालु बड़ी संख्या में सीवन नदी तट से कावड़ में जल भरकर पैदल कुबेरेश्वर धाम जाएंगे।

सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक... 11 किमी की कावड़ यात्रा

बता दें कि, 6 अगस्त की सुबह 9 बजे सीवन नदी से जल भरकर श्रद्धालु 11 किमी. पैदल यात्रा कर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। कावड़ यात्रा पंडित प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें बड़ी तादात में श्रद्धालु शामिल हुए। इंदौर भोपाल हाईवे पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर चल रहे हैं। वहीं लोगों की भीड़ से कुबेरेश्वर धाम में पंडाल भरे हुए हैं। सीहोर नगर की होटल, लॉज, धर्म शालाएं भर चुकी है।

यातायात को ध्यान में रखते हुए इंदौर-भोपाल मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। साथ ही भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया है।

### सीहोर मार्ग बंद

कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त के रात्रि 12 बजे से 6 अगस्त रात्रि 12:00 बजे तक मार्ग डायवर्सन किया गया।

## समाज प्रमुखों की बैठक का किया आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में ए.डी.आर. भवन, जिला न्यायालय परिसर में समाज प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जय पाटीदार द्वारा सभी समाज प्रमुखों को सामुदायिक मध्यस्थता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक मध्यस्थता एक प्रक्रिया है, जिसमें समुदाय के सदस्यों के बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद की जाती है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जहां एक तटस्थ मध्यस्थता, विवाद में शामिल पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। इसके साथ ही लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत तथा निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना के बारे में भी बताया गया। साथ ही उपस्थित समाज प्रमुखों से मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नाम भी आमंत्रित किए गए तथा अपने-अपने समुदायों में सामुदायिक मध्यस्थता का प्रचार-प्रसार किए जाने हेतु अपील की गई।

बैठक के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुजाल्दा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजेश राठौर, चितवन गेहलोत, अभिषेक वाणी द्वारा सहभागिता की गई।

## श्रावण मास के अंतिम सोमवार को हथिनेश्वर महादेव की निकली सवारी

माही की गूंज, आम्बुआ।

हिंदू सनातन धर्म तथा भगवान भोलेनाथ को अतिप्रिय श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शिवालयों में भूतनाथ का आकर्षक श्रंगार किया गया। दिन भर पूजा अर्चना अभिषेक किया गया तथा शाम को शिवजी की सवारी धूमधाम से निकली जा कर आरती पश्चात महा प्रसादी का वितरण किया गया।

हिंदू सनातन धर्म के पवित्र महीने सावन माह के चौथे तथा अंतिम सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक पूजन अर्चन करने हेतु भक्तों की विशेष कर महिलाओं की दिन भर भीड़ उमड़ती रही। शाम के समय शिवजी का आकर्षक श्रंगार किया गया तथा आम्बुआ के हथनेशवर महादेव की सवारी धूमधाम से बैंड-बाजों के साथ तथा बम भोले के जयकारों के साथ क़स्बे में निकाली गई। जिसका मार्ग में स्थान स्थान पर भव्य स्वागत किया गया। यह सवारी पुनः शिवालय पहुंची जहां पर पूजा अर्चना पश्चात पंडित शंकर लाल पारिख द्वारा महाआरती संपन्न की गई। महिला मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई पश्चात महा प्रसादी का वितरण किया गया।

यहां के अतिरिक्त त्रिलोकेश्वर महादेव तथा त्रिनेत्र महादेव मंदिर पुलिस थाना प्रांगण एवं संकटमोचन हनुमान मंदिर प्रांगण में स्थित शिवालय में भी दिन भर पूजा अर्चना आराधना अभिषेक का आयोजन संपन्न किए गए तथा शाम को आरती आदि संपन्न हुई।

# विक्रमादित्य के नाम से जाना जाएगा विक्रम विश्व विद्यालय

माही की गूंज, उज्जैन।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जयिनी के आचार्य महर्षि सांदीपनि के गुरूकुल स्थान उज्जैन में स्थापित विक्रम विश्वविद्यालय की वास्तविक पहचान को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय नामकरण करके पूरी कर दी।

विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद जैसे ही राज्यपाल मंगुभाई पटेल की मुहर लगेगी, वैसे ही इसकी पहचान वैश्विक हो जाएगी। इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कार्यपरिषद सदस्य राजेश सिंह कुशवाह और कुलगुरू प्रो अर्पण भारद्वाज ने मंगलवार को इस उल्लेखनीय कार्य को ऐतिहासिक बताते हुए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल, समस्त विधायकों और विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ यादव का आभार व्यक्त किया है।

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 30 मार्च 2025 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के 29वें दीक्षांत समारोह में जब उन्हें अपनी ही शिक्षा स्थली में मानद डी लिट् उपाधि से सम्मानित किया जा रहा था, उन्होंने घोषणा की थी कि यह विश्वविद्यालय, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के नाम से पहचाना जाएगा और इसके बाद तत्काल विक्रम विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद सदस्य राजेश सिंह कुशवाह ने पहल करके आपातकालीन बैठक बुलवाकर कुलगुरू प्रो अर्पण भारद्वाज की अध्यक्षता में विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित करके राज्य शासन को प्रेषित कर दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को पारित किया। गत दिवस यानी 04 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा में विधेयक पारित हो गया। इसके बाद अब विधेयक पर राज्यपाल की मुहर लगते ही विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन पहचान बन जाएगा।

उज्जैन अपनी प्राचीनता और समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र भी रहा है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद कई हस्तियों ने केंद्र सरकार से उज्जैन में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का आग्रह किया। उनका प्रस्ताव था कि विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य के नाम पर रखा जाए। जब मध्यभारत राज्य अस्तित्व में आया, तो प्रस्तावित विक्रम विश्वविद्यालय के लिए उज्जैन को चुना गया। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 01 मार्च 1957 को उज्जैन में हुई थी। विक्रम विश्वविद्यालय की आधारशिला भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा मंगलवार, कार्तिक कृष्णपक्षा चतुर्थी, विक्रमाब्द 2013 अर्थात 23 अक्टूबर 1956 को रखी गई थी। समारोह की अध्यक्षता मध्यभारत राज्य के राजप्रमुख स्वर्गीय जीवाजीराव सिंधिया ने की थी।

1956 में मध्य प्रदेश देश का नया राज्य बना और मध्यभारत को इसमें मिला दिया गया। इस प्रकार, विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। परिणामस्वरूप विक्रम विश्वविद्यालय का संशोधित अधिनियम क्रमांक 13, 1957, 16 अगस्त 1957 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया। समय-समय पर अधिनियम में कई परिवर्तन और संशोधन किए गए। 1964-65 और 1969-70 के दौरान क्रमशः इंदौर, ग्वालियर और भोपाल विश्वविद्यालयों के गठन के कारण विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में काफी कमी आई।

20 अप्रैल, 1973 को राज्यपाल ने मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के संगठन और प्रशासन में एकरूपता लाने की अनुमति दी। यह अनुमति सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 23 अप्रैल, 1973 को प्रकाशित हुई। शिक्षा विभाग की अधिसूचना 940/20/8/71 दिनांक 3 मई, 1973 द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के उपनियम क्रमांक 1 से 19 दिनांक 25.9.73 से, जबकि क्रमांक 20 से 26 और क्रमांक 27 से 31 क्रमशः 1.12.73 और 4.5.74 से मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (विक्रम विश्वविद्यालय सहित) के लिए लागू किए गए।28 जून 1985 को मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करके उसे मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया। उपरोक्त संशोधन के अनुसार, विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार को पुनः परिभाषित किया गया तथा उज्जैन संभाग के राजस्व जिलों अर्थात उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और देवास के अनुसार सीमांकित किया गया। नए क्षेत्राधिकार के कारण सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या में कमी आई तथा कुछ नए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की गई।

पिछले वर्षों में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोहों को महान विद्वानों ने संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीपी रामास्वामी अय्यर, डॉ. कालूलाल श्रीमाली, पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र, पं. कुंजीलाल दुबे, बाबू जगजीवनराम, डॉ. गोविंद नारायण सिंह, महादेवी वर्मा, इंदिरा गांधी, डॉ. सरोजिनी महिषी, डॉ. गोपाल स्वरूप पाठक, प्रो. नुरुल हसन, डॉ. हरगोविंद खुराना और डॉ. सतीश चंद्रा, एपीजे अब्दुल कलाम।

# कलेक्टर की गाड़ी पर जरा सी खरोच पर कार्रवाई बड़ी, पर बस-कार की जबरदस्त भिड़ंत में बड़ी कार्रवाई क्यों नही...? श्री डामोर






20 फरवरी 2025 को हुई इस दुर्घटना में भी कलेक्टर की गाड़ी की हुई दुर्घटना के बाद जिस तरह हुई कार्यवाही उसी तर्ज पर हो कार्रवाई की मांग पहुची जनसुनवाई में।

**माही की गूंज, झाबुआ।**

हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समस्त भारतीयों के लिए समान कानुन का दर्जा दिया गया। जिसमें कानूनी कार्रवाई के दौरान कोई उँच-नीच व नहीं कोई छोटा व बड़ा है। वहीं अगर इस कानून को तरोड़-मरोड़ कर कोई प्रभावशील अपने प्रभाव का जब कोई दुरुपयोग कर निजी द्वेषभाव के साथ कार्रवाई करता है, जिसमें उँच-नीच व छोटा- बड़ा का अंतर दिखने पर दोहरी कार्रवाई के विरोध में आवाजे बुलंद होना लाजिमी ही है।

28 जुलाई 2025 को जिस कार में कलेक्टर मेडम बैठी थी उस कार का कलेक्टर के बंगले से निकलकर एल टर्न काटते ही पीछे से आ रहे खाली 16 पहिया डंपर व कार की भिड़ंत हो गई। इसमें गलती कहां, कैसे और क्यों व किसकी गलती थी यह आज हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कलेक्टर की कार से हुई उक्त दुर्घटना के बाद भले ही दुर्घटना में कोई हताहद नहीं हुआ परंतु डंपर मालिक जिसे रेत माफिया बताकर सख्त कार्रवाई के रूप में दुर्घटना प्रकरण के अलावा उनकी या जिस संपत्ति पर उनकी ऑफिस व परिसर को सील किया गया। वहीं परिसर में करीब नाम मात्र की रेत मिली उसपर बड़ा जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं कलेक्टर की कार से टकराने वाला डंपर एमपी 13 एच 1089 जो कि खाली डंपर होने के बावजूद मौका कलेक्टर ऑफिस के सामने झाबुआ 30 घनमीटर रेत खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया...! उक्त वाहन को जप्त किया जाकर पुलिस कोतवाली झाबुआ की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।

उक्त उल्लेख कलेक्टर कार्यालय झाबुआ से न्यायालय अपर कलेक्टर की सील के साथ पत्र क्रमांक 575/ रीडर 2/ 29 जुलाई 25 को जारी हुआ।

उक्त आदेश प्रतिवेदन खनिज विभाग झाबुआ के माध्यम से डंपर मालिक शांतिलाल पिता अंबालाल बसेर निवासी प्रतापगली राणापुर को भेजा गया। जिसमें बसेर के विरुद्ध 4 लाख 56 हज़ार 2 सौ 50 रुपये का जुर्माना दर्शाया गया।

किसी भी माफियाओ को जमीदोज करने के लिए नियमित इस तरह की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाती, तो तय है उसकी सराहना जिले से लेकर प्रदेश तक होती यह सही है, और माही की गूंज भी प्रशासनिक कार्रवाई की सराहना करता। खैर, प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई सही की गई या गलत यह प्रशासन जाने पर अगर माफियाओं को जमीदोज करने के लिए उक्त कार्रवाई की शुरुआत कर आगे निरंतर रेत माफियाओ व जिले के अन्य माफियाओं के विरुद्ध यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अगर यह मंशा प्रशासन की है तो माही की गूंज उक्त कार्रवाई की सराहना करता है।

लेकिन डंपर व डंपर मालिक के विरुद्ध कलेक्टर की कार की हुई दुर्घटना के बाद प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई व की जा रही है उसे दोहरी तथा द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जाना लोगों द्वारा कहा जा रहा है।

### क्या आम नागरिक की जान व चोट, संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है...?

इसी कड़ी में गोला छोटी निवासी धनसिंह डामोर ने दोहरी कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए झाबुआ कलेक्टर सहित आरटीओ व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ को जनसुनवाई में एक शिकायत की। शिकायत में बताया कि, मैं धनसिंह डामोर निवासी ग्राम गोला छोटी (झाबुआ) 20 फरवरी 2025 को एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ। इस दिन मनीष जैन की अवैध रूप से चलाई जा रही स्लीपर बस क्रमांक एमपी 11 पी 0837 ने मेरी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। जिसमें मेरी कार पूरी तरह नष्ट हो गई तथा मेरी पत्नी के दोनों हाथ फैक्चर हो गए और मुझे भी गंभीर आंतरिक चोटे आई।

घटना के बाद संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई। परंतु आज तक न तो ड्राइवर या बस मालिक की गिरफ्तारी हुई न ही कोई मुआवजा और न ही कोई बस जप्ती या अवैधता की कोई जांच हुई। जबकि इसी जिले में कलेक्टर की गाड़ी को मामूली खरोच आई तो तुरंत डंपर चालक व मालिक पर कड़ी कार्रवाई की गई। यहां तक कि, मालिक के घर और संपत्ति सील कर दी गई।

वहीं धनसिंह डामोर ने शिकायत पत्र में प्रश्न किया कि, क्या आम नागरिक की जान व चोट, संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है...? एक ही जिले में कानून का यह दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है...? क्या बस मालिक की पहुंच और रसुक के कारण प्रशासनिक लापरवाही की जा रही है...? के प्रश्नों के साथ धनसिंह ने मांग की है कि, एफआईआर के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी और बस की जप्ती की जाए, बस की वैधता की जांच आरटीओ द्वारा की जाए और लाइसेंस निरस्त किया जाए। साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी, कलेक्टर के मामले में की गई कार्रवाई की तरह ही मेरे मामले में भी समान कानूनी कार्रवाई की जाए की मांग की।

साथ ही प्रशासन को चुनौती दी है कि, अगर जल्द उचित कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरी में यह मामला उच्च न्यायालय मानवाधिकार आयोग और मीडिया के माध्यम से उक्त मामले को उठाना पड़ेगा। खैर आगे देखना है कि, प्रशासन अपने ही खिलाफ लगे आरोपों के साथ आए जनसुनवाई में शिकायत प्रतिवेदन पर आगे किस तरह की और क्या कार्रवाई करता है...?

मामले में माही की गूंज को पीड़ित धनसिंह डामोर ने जानकारी देते हुए बताया कि, 20 फरवरी को मेरी कार से मैं, मेरी पत्नी सारिका, बेटे आरव व अर्थव तथा भानेज आशीष गामड़ जा रहे थे कि, सामने से आ रही आराधना ट्रेवल्स की बस ने जोरदार टक्कर मारकर हमारी पूरी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और हमें चोट आकर फैक्चर भी हुए। यह तो भगवान की मेहरबानी रही कि, हम बाल-बाल बच गए नहीं तो बस की टक्कर से मैं और मेरा पूरा परिवार मौत की सय्या पर सो ही जाते। धनसिंह ने कहा कि, जब कलेक्टर की गाड़ी पर जरा सी खरोच आई और किसी को चोट भी नहीं लगी तो भी बस मालिक के विरुद्ध उसकी संपत्ति पर कार्रवाई के साथ खाली डंपर होने के बावजूद उन्हें बड़ा जुर्माना दिया गया। ऐसे में उक्त बस मालिक मनीष जैन जो भी राणापुर का ही है उसके विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जैसी कार्रवाई, कलेक्टर की कार के साथ हुई दुर्घटना के बाद डंपर मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की गई।


कार्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ (म0प्र0)

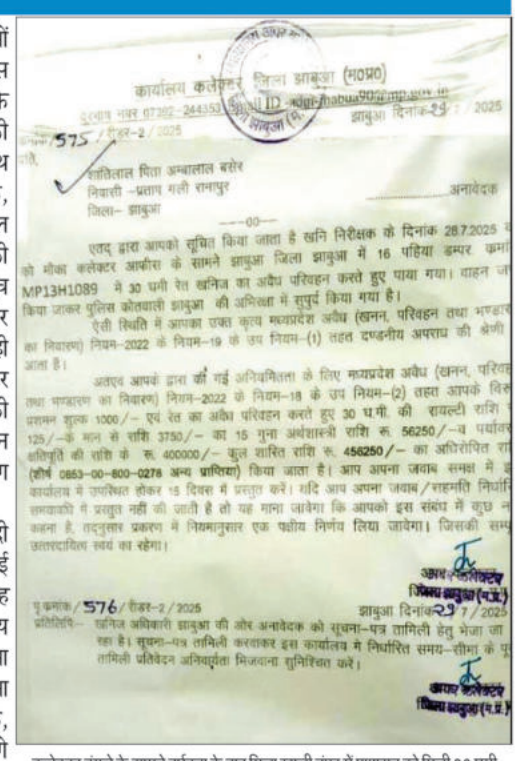

दूरभाष नम्बर 07392-244353 Email ID -adm-jhabua@mp.gov.in झाबुआ दिनांक 29/7/2025

क्रमांक/575/रीडर-2/2025

प्रति,

शांतिलाल पिता अम्बालाल बसेर
निवासी -प्रताप गली रानापुर
जिला- झाबुआ

अनावेदक

---00---

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है खनि निरीक्षक के दिनांक 28.7.2025 ... को मौका कलेक्टर आफीस के सामने झाबुआ जिला झाबुआ में 16 पहिया डम्पर क्रमां... MP13H1089 मे 30 घमी रेत खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। वाहन ज... किया जाकर पुलिस कोतवाली झाबुआ की अभिरक्षा मे सुपुर्द किया गया है।

ऐसी स्थिति मे आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश अवैध (खनन, परिवहन तथा भण्डार... का निवारण) नियम-2022 के नियम-19 के उप नियम-(1) तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी ... आता है।

अतएव आपके द्वारा की गई अनियमितता के लिए मध्यप्रदेश अवैध (खनन, परिव... तथा भण्डारण का निवारण) नियम-2022 के नियम-18 के उप नियम-(2) तहत आपके विरु... प्रशमन शुल्क 1000/- एवं रेत का अवैध परिवहन करते हुए 30 घ.मी. की रायल्टी राशि ... 125/- के मान से राशि 3750/- का 15 गुना अर्थशास्ती राशि रू. 56250/- व पर्याव... क्षतिपूर्ति की राशि के रू. 400000/- कुल शास्ति राशि रू. 456250/- का अधिरोपित रा... (शीर्ष 0853-00-800-0278 अन्य प्राप्तियां) किया जाता है। आप अपना जवाब समक्ष में इ... कार्यालय में उपस्थित होकर 15 दिवस में प्रस्तुत करें। यदि आप अपना जवाब/सहमति निर्धारि... समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ न... कहना है, तदनुसार प्रकरण में नियमानुसार एक पक्षीय निर्णय लिया जावेगा। जिसकी सम्पू... उत्तरदायित्व स्वयं का रहेगा।

अपर कलेक्टर
जिला झाबुआ (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/576/रीडर-2/2025 झाबुआ दिनांक 29/7/2025

प्रतिलिपि- खनिज अधिकारी झाबुआ की ओर अनावेदक को सूचना-पत्र तामिली हेतु भेजा जा रहा है। सूचना-पत्र तामिली करवाकर इस कार्यालय मे निर्धारित समय-सीमा के पू... तामिली प्रतिवेदन अनिवार्यता भिजवाना सुनिश्चित करें।

अपर कलेक्टर
जिला झाबुआ (म.प्र.)

कलेक्टर बंगले के सामने दुर्घटना के बाद मिला खाली डंपर में प्रशासन को मिली 30 घमी रेत और दिया 456250 का जुर्माना।

# भाजपा सरकार और बेखौफ भ्रष्टाचार...!

## उदयगढ़ के खंड शिक्षा कार्यालय में एक और भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा

**माही की गूंज, उदयगढ़ (कनास)। खलील मंसूरी**




किसी भी सरकार की वास्तविक कार्य प्रणाली यह होती है कि, उनकी सरकार में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार व अनिमित्ताए न हो। अगर ऐसा कोई भूल से भी उनकी सरकार में कर दे तो उन अनियमित्ता करने वाले व भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले को ऐसा सबक सिखाया जाए कि, उससे नसीहत लेकर कोई अनियमित्ता व भ्रष्टाचार करने में हजार बार सोचने को मजबूर हो जाए। वहीं सरकार की उक्त कार्य प्रणाली के साथ ही आम लोगों को हक मिले व उनके साथ अन्याय न होकर सरकार के प्रति असीम विश्वास आम जनता का रहे। लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बेखोफ हो रहा है जिसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। जिसके कारण अब अजब मध्य प्रदेश में गजब का भ्रष्टाचार का नाम दिया जाने लगा है।

हाल ही की कुछ ऐसे भ्रष्टाचार की बात करें जिसमें शहडोल जिले में निपानिया व स्कंदी की शासकीय स्कूल में 24 लीटर ऑयल पेंट करने हेतु 443 मजदूर व 215 मिस्त्री लगाकर 3 लाख 38 हज़ार रुपये खर्च करने का मामला सुर्खियों में आया।

झाबुआ में जिस रामा जनपद से अच्छे कार्यो के नाम पर झाबुआ कलेक्टर, प्रधानमंत्री से सम्मानित हुए, उसी जनपद में सम्मान को पलीता लगाते हुए एक करोड़ के करीब का भ्रष्टाचार उजागर हुआ।

गिरधर ठाकरे।


रामसिह सोलंकी।


भरत नामदेव।

अगर अलीराजपुर जिले की बात करें तो इस जिले में भी कई अनियमित्ताएं और भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं। अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ (कनास) की ही बात करें तो यहां 2020 में करीब 17 करोड़ का भ्रष्टाचार खंड शिक्षा कार्यालय में उजागर हुआ था। जिस मामले में करीब 14 अधिकारी व बाबुओं पर स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और मामला अब भी मान्य न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आने के बाद भी जो सख्त कानूनी कार्रवाई ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध होना चाहिए, शायद सरकार वह कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। नतीजन ये हो रहा है कि, भ्रष्ट, भ्रष्टाचार के नए-नए निजात खोज कर बेखोफ होकर बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर सरकार की कार्य प्रणाली को ही चिड़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

नतीजन उदयगढ़ (कनास) की खंड शिक्षा कार्यालय में भ्रष्ट नुमाईंदे ने फिर भ्रष्टाचार का एक नया निजात कर करीब सवा करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला फिर से सामने आया है।

उदयगढ़ में वेतन-भत्तों के आहरण में 1.27 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला पकड़ा है। इसके अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने पात्र कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों के नाम पर भी बड़ी राशि ट्रांसफर की। इतना ही नहीं आवास और अन्य भत्तों के नाम पर भी शिक्षकों को उनकी पात्रता से अधिक राशि का भुगतान किया गया। करीब सवा करोड़ से अधिक का भुगतान संदिग्ध तरीके से होने की बात सामने आई थी। कुछ मामलों में बैंक रिकॉर्ड के अनुसार भुगतान पाने वालों के नाम अलग थे और एक ही खाते में कई लोगों के नाम से भुगतान किया गया।

एक कर्मचारी को 21 हजार रुपये का गृह भाड़ा भत्ता दिया गया, जबकि उसकी वास्तविक पात्रता बहुत कम थी। इसी तरह दैनिक अतिथि शिक्षकों को 54 हजार रुपये तक का भुगतान कर दिया गया, जबकि उनका मूल वेतन सिर्फ 6080 रुपये है।

### जांच के बाद हुई निलंबन की कार्रवाई

यह गंभीर अनियमित्ता सामने आने के बाद 25 जुलाई को कोष एवं लेखा विभाग ने आलीराजपुर कलेक्टर को जांच करने और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने बीईओ कार्यालय के 2018-19 तक के सभी लेन-देन की जांच के आदेश दिए। कलेक्टर डॉ. बेडेकर के प्रतिवेदन के आधार पर संभागायुक्त दीपक सिंह ने कार्रवाई करते हुए उदयगढ़ के तत्कालिन बीईओ गिरधर ठाकरे, भारत नामदेव तथा वर्तमान में प्रभारी बीईओ रामसिंह सोलंकी को निलंबित कर दिया। इन तीनों पर डीडीओ कोड 4912506050 के तहत वित्तीय अनियमित्ता और कपटपूर्ण भुगतान में लापरवाही की प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई है। गिरधर ठाकरे और रामसिंह सोलंकी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय आलीराजपुर और भरत नामदेव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय धार नियत किया गया है।

### कौन कब तक रहा उदयगढ़ में

खंड शिक्षा अधिकारी बनकर भरत नामदेव 8 जून 2020 को उदयगढ़ में पदस्थ हुए थे। इनका कार्यकाल करीब 5 माह 19 दिन का रहा। वर्तमान में प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर निसरपुर (धार) है।

खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में गिरधर ठाकरे ने 27 नवंबर 2020 को चार्ज लिया था। ये करीब 2 वर्ष 23 दिन कार्यरत रहे। वर्तमान में प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणी (आलीराजपुर) है।

19 अगस्त 2023 को रामसिंह सोलंकी को बीईओ का प्रभार दिया गया था, वे बीआरसी भी है। वे मूल रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षक है। अब तक उदयगढ़ में काम देख रहे थे।

### गलत काम करने वालों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने कहा, कोई भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। उदयगढ़ के मामले में भी तीन कर्मचारियों को हटाया गया है। उदयगढ़ खंड शिक्षा कार्यालय में सामने आए मामले की जांच की जा रही है।

# त्यौहारों के आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग का प्रपंच शुरू

## जिले में नमूने जांच की कोई सुविधा नहीं, भोपाल से नतीजे आने में लगते है महीनों

## त्यौहारिया सीजन में बड़े प्रतिष्ठानों पर नजर, साप्ताहिक हाट बाजारों को कर देते है नजरअंदाज

**माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसूरी**

कहते है फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, इसी तरह मिलावट के दौर में शुद्धता की इच्छा भी ना की जाए तो ठीक ही होगा। क्योंकि प्रदेश में खाद्य सामग्री को लेकर सरकार और तंत्र बिल्कुल भी गंभीर तो दिखाई नहीं दे रहे है। जब-जब त्यौहारिया सीजन आता है प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा विभाग का अमला बाजारों की खाक छानता नजर आता है। मगर बावजूद इसके खाद्य सुरक्षा विभाग के हथपल्ले कुछ नहीं। इसका भी एक बहुत ही रौचक और बड़ा कारण है। फिलहाल त्यौहारों के मद्देनजर बाजारों में खाद्य सामग्री और मिठाईयों की भरमार होने वाली है। मगर इनकी शुद्धता को लेकर न तो सरकार चिंतित है और ना ही सरकारी तंत्र। हां यह जरूर है कि, कहीं-कहीं कुछ जगहों पर बड़ी कार्रवाईयां देखने को मिल जाती है। इनमें भी अधिकतर में दुग्ध उत्पादों की ही अधिक मात्रा होती है, जैसे मावा, पनीर और दूध से बने तमाम तरह के व्यंजन शामिल होते है। इसके अलावा बहुत कम ही ऐसा होता है कि, किसी अन्य खाद्य सामग्री की मिलावट या कालाबाजारी पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिले।

वैसे यह सीजन त्यौहारिया सीजन माना जाता है। इस सीजन में लगातार त्यौहार एक के बाद एक लगे रहते है। श्रावण के बाद रक्षा बंधन, जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्यौहारों के चलते बाजारों में खाद्य सामग्री की पूछ-परख अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसलिए इसकी गुणवत्ता और गारंटी की सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश भर में एक अलग ही विभाग काम पर लगा हुआ है। जिसे खाद्य सुरक्षा विभाग कहा जाता है। वैसे तो इस विभाग की ड्यूटी साल भर यही रहती है कि, वह बाजार में बिक रहे अमानक खाद्य पदार्थों की जांच कर विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई करे। लेकिन यह विभाग साल में महज कुछ समय के लिए ही सुर्खियों में नजर आता है। त्यौहारिया सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग का अमला गांव-गांव पहुंचता और खाद्य सामग्री के नमूने इकठ्ठा करता नजर आता है। यह और बात है कि, विभाग द्वारा लिए गए इस तरह के नमूनों की जांच कब आती और कहां गायब हो जाती है। इस पर विडम्बना यह कि, खाद्य सुरक्षा विभाग के पास खाद्य सामग्रियों के नमूने जांचने की कोई सुविधा जिला मुख्यालयों पर मौजूद नहीं है। जांच के लिए इकट्ठे किए गए नमूनों की त्वरित जांच भी संभव नहीं है। कारण यह कि, पूरे प्रदेश में खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच के लिए प्रदेश में केवल एक ही प्रयोगशाला मौजूद है। वह भी राजधानी भोपाल में है। प्रदेश भर के जांच नमूने यहीं आकर सरेंडर हो जाते है। जांच हो भी जाए तो रिपोर्ट जिला मुख्यालयों तक पहुंचने में महीनों का समय लग जाता है।

पश्चिमी मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल जिलों में स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय दिखाई देती है। क्योंकि यहां देश के सबसे गरीब जिले झाबुआ और आलीराजपुर है यह माना जाता है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के चलते यहां खाद्य सामग्री में शुद्धता का पैमाना सरकार या उसके तंत्र के लिए मानों कोई महत्व नही रखता। झाबुआ जिला मुख्यालय पर खाद्य सुरक्षा विभाग है तो सही लेकिन उसकी उपस्थिति सुविधाओं के अभाव में नगण्य है। उस पर सितम यह कि, अफसरशाही अधिकारी ज्यादातर खानापुर्ति पर ही जोर देते नजर आते है। नतीजा यह है कि, सिर्फ त्यौहारिया सीजन में ही विभागीय अमला बाजारों की खाक छानता फिरता है। खाद्य सामग्रियों की दुकानों से नमूने लिए तो जाते है, मगर महीनों लंबी जांच प्रक्रिया के बाद परिणाम क्या सामने आते है यह कभी मीडिया में उजागर नहीं किया जाता। स्थानीय स्तर पर विभाग के पास कोई जांच उपकरण शायद है ही नहीं, इसी के चलते नमूने भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजे जाते। होता यह है कि, जिस समय और स्थिति में नमूने भेजे जाते उसकी रिपोर्ट आने में महीनों का समय लग जाता। इतने समय में त्यौहारिया सीजन निपट जाता और शुद्ध-अशुद्ध सभी तरह की खाद्य सामग्री रिपोर्ट आने के पहले ही बाजार में खप जाती। शुद्धता की कोई बात नहीं लेकिन अशुद्ध सामग्री के बाजार में खपने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ आमजन का ही होता है। ऐसे कई उदाहरण है जो इस बात को प्रमाणित भी करते है। कुछ वर्ष पूर्व जिला मुख्यालय पर ही राष्ट्रीय पर्व के दौरान एक्सपाईरी डेट की मिठाईयां बंट जाती है और किसी को कानों-कान खबर भी नहीं लगती। जब इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ तो फिर अधिकारी अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए जांच का ढकोसला करते दिखाई दिए थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिला प्रशासन और उसका खाद्य सुरक्षा विभाग कितना गंभीर है। हालातों में अब भी कोई बदलाव देखने को नही मिल रहा है।

हांलाकि खाद्य सुरक्षा विभाग की ड्यूटी है कि, वह हमेशा वर्ष भर इस बात पर निगरानी रखे कि, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मिलावटी या नकली खाद्य सामग्री तो जिलेवासियों को नहीं परोसी जा रही है। मगर अफसोस की अधिकांश खाद्य सुरक्षा विभाग सिर्फ त्यौहारिया सीजन में ही बाजारों में नमूने इकठ्ठा करता नजर आता है। जबकि आदिवासी बाहुल जिला होने के चलते विभाग को बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात करें जिले में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों की तो यह खाद्य सुरक्षा विभाग व जिला प्रशासन की पूरी की पूरी पोल खोलकर रख देगा। त्यौहारिया सीजन न भी हो तो जिले में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार ऐसी जगह है जहां आप कुछ भी खपा सकते है। चाहे फिर वह शुद्ध हो या अशुद्ध, सड़े हुए तेल में बनने वाली सामग्री हो या सड़े हुए फल, नकली सर्फ-सोड़ा हो या मिलावटी मसाले। नशीली नकली ताड़ी हो या अवैध रूप से बिकता मांस-मटन, इन हाट बाजारों में आपको सबकुछ आसानी से देखने को मिल जाएगा। मगर अफसोस यह कि, जिले में बैठा खाद्य सुरक्षा विभाग कभी इन साप्ताहिक हाट बाजारों की ओर रूख नहीं करता। दबी जुबान में बताने वाले बताते है कि, यहां मामला कुछ और ही है। अगर खाद्य सुरक्षा विभाग हाट बाजारों में भटके तो कोई घांस भी ना डाले। मगर त्यौहारिया सीजन में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर जाने से कम से कम मिठाई का जुगाड़ तो पक्का ही है।

वैसे विभाग द्वारा जारी हर प्रेसनोट में कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्रवाई का हवाला दिया जाता है। मगर विभाग कभी कलेक्टर से सहयोग लेकर जिला मुख्यालय पर नमूनों की प्राथमिक जांच का प्रबंधन क्यों नहीं करवा पा रहा है। या फिर कलेक्टर जब खाद्य सुरक्षा विभाग से जांच और कार्रवाई की उम्मीद रखती है तो फिर वे विभाग को जांच हेतु सुविधाएं क्यों उपलब्ध नही करवा पा रही है, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है।

खैर जो भी हो लेकिन अभी त्यौहारिया सीजन है और मिलावट खोर या नकली माल खपाने वाले इस सीजन का पूरा फायदा उठाएंगे और खाद्य सुरक्षा विभाग हाथ पर हाथ धरे तमाशाबीन बना रहेगा। क्योंकि वह नमूने लेने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता।

प्रथम दृष्टिया अगर विभाग नमूने लेने के साथ ही माल भी जप्त कर लेता है और नमूने की जांच मानकों पर खरा उतर जाती है तो जप्त की गई सामग्री के नुकसान का भुगतान कौन करेगा? दूसरी स्थिति में अगर नमूना लेकर माल जप्त नहीं किया गया और जांच में वह अमानक पाया गया तो फिर जब तक जांच रिपोर्ट आएगी विक्रेता तब तक अपना पूरा अमानक माल बाजार में खपा चुका होगा। ऐसी स्थिति में यह समझ से परे है कि, आखिर खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहे है। या फिर इस तरह की कार्रवाई का कोई और ही मकसद है, जो आमजन के हितों से परे और अधिकारियों के हितों के समीप हो...?

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422